हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 मार्च, 1979

(प्रथम बैठक)

खण्ड 1 अंक 13

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 22 मार्च, 1979

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(13)1
सदस्यों को निकालना	(13)9
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(13)10
अध्यक्ष द्वारा रूलिंग –	
सदन में भाशा के प्रयोग संबंधी	(13)16
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(13)18
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(13)23
औचित्य प्रश्न –	(13)31
एडमिट किये हुए ध्यानाकर्शण प्रस्ताव को रि–कंसिडर करने सम्बन्धी बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट	(13)34
वर्श 1979–80 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)	(13)37

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 22 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रायः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब सवाल होंगे।

Mini Aerodrome

***1018. Sh. Jai Narain**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Mini Aerodrome at Rohtak, if so, the time by which it is likely to start functioning?

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल): जी हां। राज्य सरकार ने रोहतक जिले में हवाई पट्टी बनाने का फैसला किया है। आशा की जाती है कि अगले वित्त वर्श यानी 1979–80 के अन्त तक इस हवाई पट्टी से आप्रेशन प्रारम्भ हो जायेंगे।

चौ. संत कंवर: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो छोटा हवाई अड्डा रोहतक में बनाने की सरकार ने स्कीम बनाई है क्या इस हवाई अड्डे पर छोटे हवाई जहाज ही उत्तर सकेंगे या बड़े हवाई जहाज भी उतारने का प्रावधान होगा?

चौ. देवी लाल: इस पर छोटे हवाई जहाज ही उत्तर सकेंगे।

श्री टेक राम: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो भिवानी के अन्दर हवाई पट्टी बनाई गई है उसके लिए छोटे किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी लेकिन उनको आज तक उस जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया तो क्या मुख्या मंत्री जी उनको मुआवजा दिलाने की तरफ ध्यान देंगे?

चौ. देवी लाल: वैसे तो इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए लेकिन जहां तक मुआवजे का ताल्लुक है मुआवजा तो उन्हें दिया जाना चाहिए था, यदि ऐसा कोई केस नोटिस में लाया जाएगा तो बाकायदा उसका जवाब दिया जाएगा।

श्री शमशेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा सरकार का कोई दूसरा जहाज खरीदने का विचार है?

श्री अध्यक्ष: यह सवाल मैंन सवाल से सम्बन्धित नहीं है।

चौ. देवी लाल: अध्यक्ष महोदय, यह पालिसी मैटर है इसलिए मैं इसका जवाब दूंगा। जहां तक इस सरकार का ताल्लुक है वह हवाई जहाज में सफर करने के हम में नहीं है लेकिन क्योंकि मेरे मौजिज दोस्त श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला की पार्टी ने पहले से हमारे जिम्मे यह हाथी डाल दिया था इसलिए उससे फायदा उठाने की हमने स्कीम बनाई है। हम पंजाब से मिल कर कुछ ऐसी कार्पोऐशन बनाने की सोच रहे हैं ताकि इस पर जो खर्चा हुआ है इसको किराये के रूप में वसूल करके पूरा किया जा सके।

श्री फतेह चन्द विज: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि रोहतक के अन्दर हवाई पटरी बनाने का निर्णय किया गया है तो क्या दूसरे जिलों के हैडक्वार्टज पर भी हवाई पटरियां बनाने की सरकार की कोई योजना है?

चौ. देवी लाल: पोजीशन यह है कि जितनी हवाई पटरियां पिछली सरकार ने बनाई थीं, हम उनको पूरा कर रहे हैं, नई पटरियां बनाने की योजना अभी तक कोई नहीं है। जो पिछली सरकार ने पटरियां बनाई थीं वे उन्होंने किसी और उददेश्य से बनाई होंगी लेकिन हम इनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये स्प्रे करने के काम भी आ सकती हैं। इस वक्त भिवानी में और नारनोल में हवाई पटरियां हैं। बहादुरगढ़ में भी कोशिश की गई थी लेकिन वह बन नहीं सकी। इसके अलावा जींद में और कालका में भी हैं। वे सब जिस हालात में है उन्हे

सरकार ठीक करने की कोशिश करेगी ताकि उनको काम में लाया जा सके।

चौ. नारायण सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रोहतक के रन–वे का एरिया कितना है?

चौ. देवी लाल: अध्यक्ष महोदय, रोहतक का रन वे चार हजार फुट लम्बा है और 6 सौ फुट चौड़ा है और इसका टोटल एरिया 50 एकड़ है।

लाला बलवंत राय तायल: अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि कार्पोरेशन की जो बात उन्होंने बताई है क्या यह पंजाब और हरियाणा दोनों मिल करके बनायेंगे?

चौ. देवी लाल: इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं।

डा. बृज मोहन गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह जानता हूं कि जो रोहतक में मिनिएरोड्रोम बना रहे हैं उस पर कितना खर्च आएगा?

चौ. देवी लाल: जो एरोड्रोन रोहतक में बनाया है इस पर एक लाख रूपए तो जमीन पर लगेगा, एक लाख रूप्या वायरिंग पर लगेगा और 12 लाख रूपया अड्डे के बनारे पर खर्च होगा यानी कुल खर्चा 14 लाख रूपया होगा।

चौ. हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मिनि एरोड्रोम के लिए जो जमीन एक्वायर की गई है वह कहां से की गई है?

चौ. देवी लाल: यह रोहतक के नजदीक ही है।

श्री सुमेर चन्द भट्ट: अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो पटरी बन रही है मुख्यतः इसका इस्तेमाल किस काम के लिए होगा?

चौ. देवी लाल: यह पटरियां पहले जिस उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी वह तो सैरे स्पार्ट के लिए थीं लेकिन अब ये पटरियां इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। जब मुनासिब होगा तभी हवाई जहाज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर दौरे पर जाता हैं तो सिक्योरिटी प्वायंट आफर व्यू से उसकी कार के पीछे सिक्योरिटी स्कवैड होता है और जहां उसने जाना होता है वहां भी, वे रास्ते में भी सिक्योरिटी प्वायंट आफ व्यू से पुलिस की डियूटी लगती है। सारे अफसर वहां खड़े इंतजार करते रहते हैं। चाहे मैं वहां जाने की सूचना दूं या न दूं लेकिन उनको पहले ही पता लग जाता है और वे इंतजार में खड़े रहते हैं। इसलिए उस खर्चे के मुकाबले में अगर हवाई जहाज से जाया जाए तो कम खर्चा पड़ता है। इसलिए एक तो हवाई जहाज का यह इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा फसल बचाने के लिए स्प्रे के काम भी आता है। मैं इस लिहाज से श्री सुरजेवाला की पार्टी का

थोड़ा सा शुक्रिया भी करता हूं क्योंकि क्रिटिसिज्म तो ये ले गए और फायदा हमें मिल गया। जहां हवाई पट्टी बनी हुई है वहां दूसरे स्प्रे वाले हवाई जहाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं यह काफी काम की चीज है। इसका फायदा उठाने की सरकार पूरी कोशिश करेगी।

लाला बलवंत राय तायल: अध्यक्ष महोदय, म्या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि पंजाब के साथ जितनी हमारी जिम्मेदारी है उस सब में झगड़ा चल रहा हे तो यह नई कार्पोरेशन पंजाब के साथ बनाने का सरकार से कैसे इरादा कर लिया?

चौ. देवी लाल: यह सवाल मेन सवाल से सम्बन्ध नहीं रखता।

कामरेड शंकर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चण्डीगढ़ से सिरसा हवाई जहाज द्वारा जाने का कितना खर्च आता है?

चौ. देवी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ी कोशिश की थी कि इसको साथ ले चलू लेकिन इनकी किस्मत में ऐसा नहीं लिखा है।....(हंसी)..... जहां तक खर्चे का ताल्लुक है दूसरी स्टेटस में 750 रूप्ये फी घंटे के हिसाब से चार्ज किया जाता है जैसे राजस्थान में और यू.पी. में। उनके पास भी अपने जहाज हैं लेकिन हमारे यहां 1500 रूपए फी घंटे के हिसाब से चार्ज किया जाता है। हमारे हवाई जहाज को अगर कोई किराये पर ले जाना चाहे

तो ले जा सकता है लेकिन दूसरों के मुकाबले में हमारे यहां किराया डब्ल है। अगर इस खर्चे को देखा जाए तो भी चीफ मिनिस्टर का जो खर्चा सड़क के रास्ते पड़ता है वह इससे ज्यादा ही पड़ता है और हवाई जहाज का कम पड़ता है।_____ पहले जब हवाई जहाज में सफर किया जाता था तो खाली कारें भी सड़क से भेजी जाती थीं ताकि सी.एम. उससे फायदा उठा सके। अब सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि खाली गाड़ियां न ले जाई जाएं और फिजूल का खर्चा न हो।

Embezzlement in Panchayat Fund

***1130. Sh. Fateh Chand Vij**: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state –

(a) the total number of embezzlement cases in the Panchayat funds that came to the notice of the State Government during the period from 1-4-77 to 31-12-78;

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above got registered with the Police; and

(c) whether any Government employees have been found guilty in the cases referred to in part (a) above; if so, the action taken or proposed to be taken against such delinquent officials?

Mr. Speaker: Extension has been asked fro in respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection reads as under –

“Bir Singh

D.O. No. CA-2-79/9569

Dated 19-3-79

Minister,

for Development & Panchayat Deptt.

Haryana, Chandigarh.

Subject: Starred Assembly Question No. 1130 by Sh. Fateh Chand Vij, M.L.A.

My dear,

The Starred Assembly Question No. 1130, asked by Sh. Fatech Chand Vij, M.L.A. has been fixed for answer on 22-3-79. The reply to the Assembly Question is not ready as the required information is awaited from the Deputy Commissioners.

I shall be grateful if you kindly extend the time for answering the question under proviso (ii) of Rule 41 of the Rules of procedure and conduct of business in the Haryana Legislative Assembly. This question may be included in the list of questions for any date after one month.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Bir Singh)

Col. Ram Singh,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

तारांकित प्रश्न संख्या 1164

यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि माननीय सदस्य, राव दलीप सिंह, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Drinking Water Schemes

***1091. Swami Adityavesh**: Will the Minister for Public Works be pleased to state –

(a) the total amount received for Drinking Water Schemes from the World Bank during the period from January, 1977 to February, 1979; and

(b) the Constituency-wise details of the amount being spent on Drinking Water Schemes out of the amount as referred to in part (a) above?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(ए) शून्य।

(बी) प्रश्न पैदा नहीं होता।

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार से पूछा था कि विश्व बैंक से हरियाणा सरकार को वाटर सप्लाई स्कीम्ज के लिए कितना पैसा मिला है। इन्होंने इसका जवाब दिया है ''शून्य''। यही सवाल स्वामी अग्निवेश ने, अगस्त–सितम्बर के सैशन में पूछा था और इस पर आधे घंटे की बहस की मांग भी की थी लेकिन सरकार ठीक से जवाब नहीं देती। मुझे समझ में नहीं आता कि ये हाउस में सच्चाई क्यों नहीं रखना चाहते। (व्यवधान) यह बतायें कि कितना रूपया वर्ल्ड बैंक से पानी की स्कीमों के लिए मिला है?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। वर्ल्ड बैक ने कोई पैसा नहीं दिया। वर्ल्ड बैंक ने 190 करोड़ रूपया इरीगेशन डिपार्टमैंट को दिया है जिसमें 10 करोड़ रूपये का प्रोवीजन ड्रिंकिग वाटर सप्लाई स्कीम्ज के लिऐ भी है। वर्ल्ड बैंक ने हमें कोई पैसा नहीं दिया, गवर्नमैंट आफ इंडिया को दिया है। हम खर्चा करते चले जाएंगे, खर्चे का बिल भेंजेंगे और वर्ल्ड बैक उस पैसे को गवर्नमैंट आफ इंडिया को रिइम्बर्स करेगा। अब तक 40 लाख रूपये के बिल भेजे जा चुके हैं जिसमें से 27 लाख रूपया हमें मिलने वाला है। यह रूपया कब मिलेगा, इसके बारे में

कुछ नहीं बताया जा सकता। जब हमारे पास अभी पैसा आया ही नहीं है तो हम कैसे कह दें कि मिला है। यह तमाम खर्चा प्लान से होगा क्योंकि प्लान में खर्चा करने के लिए प्रोवीजन है। हम जितना खर्चा करेंगे उसका बिल गवर्नमैंट आफ इंडिया को देंगे। गवर्नमैंट आफर इंडिया ने 50 परसैंट देना माना है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 60 परसैंट तक मिल जाए। जो बिल भेजे हैं उनमें से 27 लाख रूपया, मुझे उम्मीद है 31 मार्च तक मिल जाएगा, लेकिन यह बात सही है कि अभी तक हमें कोई पैसा नहीं मिला है।

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मुझे कहा था कि 1 करोड़ रूपये से ज्यादा मिल चुका है (व्यवधान)

श्री लछमन: कब कहा था?

स्वामी आदित्यवेश: अभी कुछ समय पहले कहा था (व्यवधान) सितम्बर के महीने में हमारे साथी स्वामी अग्निवेश ने पूदा था तो इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ रूपया आया है जिसमें से 44 लाख रूपया मंत्री जी ने अपने हल्के में खर्च कर लिया और बाकी.....

श्री अध्यक्ष: अगर आप यही सवाल पूछना चाहते थे तो पहले नोटिस देते। (व्यवधान) आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में सवाल पूछा है और उसका जवाब मंत्री महोदय ने दिया है। (व्यवधान)

चौ. हरस्वरूप बूरा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वाटर सप्लाई स्कीम पर लोगों से जो बैनिफिशरी शेयर लिए जाते थे, क्या ये शेयर देने से बैनिफिशरीज को एग्जम्पट कर दिया है या अभी तक जारी है?

श्री लछमन सिंह: जारी है लेकिन जहां सब–माउंटेनस एरियाज हैं, जैसे गुड़गांव जिले का एरिया है, वहां पर शेयर मुआफ है। इस प्रकार की एरियाज की कई कैटेगरीज बनी हुई हैं, उनमें से कुछ कैटेगरीज में मुआफ है लेकिन सारी स्टेट में मुआफ नहीं है।

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा, मैंने शार्ट नोटिस क्वैश्चन दिया था और सरदार लछमन सिंह जी ने कहा था कि इसका जवाब दूंगा। इस प्रश्न करे पूछे हुए 6 महीने हो गये हैं, कार्यालय से दो–तीन रिमाइंडर भी दिए जा चुके हैं लेकिन मंत्री महोदय ने आज तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया?

श्री लछमन सिंह: स्वामी जी का एम.एल.ए. बने हुए दो साल हो गये हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि जो सवाल पिछले सैशन के बाकी रह जाते हैं उनका जवाब लेने के लिए कंसर्न्ड मैम्बर को दोबारा नोटिस देना पड़ता है, तभी अगले सैशन में उनका जवाब आयेगा।

Mr. Speaker: In this particular case, I would request the Hon. Minister to kindly send the answer to that question. It was a commitment.

श्री लछमन सिंह: ये दोबारा लिख कर दे दें, हम अभी जवाब दे देंगे। (व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि स्वामी जी जितनी बात हाउस में करते हैं, अगर इससे आधी बात सदन से बाहर मुझे मिलकर कर लें, या मुझे मेरे कमरे में मिलें तो सारा मसला हल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। इस पर्टिकुलर केस में, जो सवाल 6 महीने पहले पूछा था इसका जवाब जल्दी ही प्राप्त किया जाएगा और मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस सवाल का जवाब स्वामी जी को जल्दी से जल्दी दिया जाए।

श्री लछमन सिंह: स्वामी जी मुझे बता दें, मैं अभी जवाब दे दूंगा। (व्यवधान)

लाला बलवन्त राय तायल: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत जो रूपया खर्च कर रहे हैं, क्या इसकी कोई प्रायरिटी बनी हुई है?

श्री लछमन सिंह: सारे हरियाणा में जितने विलेजिज हैं उनमें से प्रायरिटी उन गांवों को दी जाती है जहां पानी की

किल्लत है, खारा पानी है या गांव वालों को पानी दूर से लाना पड़ता है।

चौ. हरिचन्द हुड्डा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि गांवों को पानी देने के लिए सरकार ने जो ग्रुपिंग स्कीम बनाई थी, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे?

श्री लछमन सिंह: बगैर ग्रुपिंग के हम पानी देते ही नहीं है। हां, हमने पोलिटिकल ग्रुपिंग नहीं की है (व्यवधान) वाटर सप्लार्ठ करने के लिए ग्रुपिंग स्कीम लागू है।

श्री अध्यक्ष: मैं मैम्बर साहेबान से रिक्वैस्ट करूंगा कि मेन क्वैश्चन से संबंधित सप्लीमैंटरी ही पूछें। मेन क्वैश्चन यह है कि वर्ल्ड बैंक से सरकार ने कितना पैसा लिया। इस क्वैश्चन से मिलता–जुलता क्वैश्चन पूछें तो ठीक रहेगा।

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि 40 लाख रूप्या वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत खर्च किया है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह रूपया कहां–कहां खर्च किया है?

श्री लछमन सिंह: 40 लाख रूपये का बिल वर्ल्ड बैंक प्रोजैक्ट के तहत भेजा है लेकिन खर्चा ज्यादा हुआ है। फण्डज किस तरह से अलाट किए हैं, वह इस प्रकार है–

कलायत	10.00 लाख
किलोई	5.50 लाख
कलानौर	1.00 लाख
मैहम	5.50 लाख
हसनगढ़	3.00 लाख
बहादुरगढ़	5.00 लाख
बड़ोदा	3.00 लाख
गोहाना	2.00 लाख
नारायणगढ़	14.50 लाख
कालका	12.50 लाख
नूह	9.00 लाख
ताउड़	10.00 लाख
हथीन	7.00 लाख

गजराई	30.00 लाख
आदमपुर	12.00 लाख
भट्टूकलां	29.50 लाख
बरवाला	2.00 लाख
फतेहाबाद	1.00 लाख
नारनौंद	12.50 लाख
सिरसा	1.00 लाख
रोड़ी	14.50 लाख
डबवाली	9.50 लाख

Vigilance Committee for Non-officials

***1080. Rao Ram Narain**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the number of complaints so far received by the Vigilance Committee for non-officials constituted by the State Government.

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above respect of which the investigation has been completed;

(c) whether any recommendation has been received by the Government from the said Committee; if so, the action taken thereon;

(d) whether any complaints have been received by the said Committee against any M.P./M.L.A., or Minister;

(e) if so, the action taken thereon; and

(f) the amount of T.A. and D.A. paid to each member of the said Committee togetherwith the expenditure incurred by the Government on the maintenance of official car allotted to it?

Irrigation & Power Minister (Sh. Verender Singh):

(a) 781

(b) 456

(c) The recommendations of the Vigilance Committee were received in 118 cases……

सदस्यों को निकालना

स्वामी आदित्यवेश: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय से कहा जाए कि ये हिन्दी में जवाब दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: देखिए मैम्बर साहेबान, मैं आपसे फिर रिक्वैस्ट करता हूं। (शोर) आर्डर प्लीज। दोनों जुबान, इंगलिश या हिन्दी में किसी मैम्बर को बोलने की पूरी आज्ञा है। इस बेसिज पर मैं कतई इंट्रप्शन हाउस में टौलरेट नहीं करूंगा।

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, अगर ये हिन्दी में बोलें तो अच्छा रहेंगा।

Mr. Speaker: Swami ji, I will name you.

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल नम्र निवेदन कर रहा हूं।

Mr. Speaker: I name Swami Aditya Vesh. (Interruptions) He should withdraw from the House.

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिए।

(इस मसय सारजैन्ट एट आर्मज स्वामी आदित्य वेश जी की सीट पर गए)

स्वामी आदित्यवेश: ठीक है हम बाहर चले जाते हैं।

(इस समय स्वामी आदित्य वेश जी सदन से बाहर चले गए)

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, मिनिस्टर साहब, अब जवाब दे रहे हैं। हाउस में डैकोरम और अनुशासन कायम रखना मेरी डियूटी है। इस काम में मैं वेरियस पार्टीज और ग्रुप्स के जो लीडर्ज हैं उनका भी सहयोग चाहता हूं। वे हाउस में डैकोरम और अनुशासन रखने में मेरी मदद करें। (शोर) मैं हाउस मैं डैकोरम और अनुशासन पूरी तरह रखूंगा। इस समय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। मैं मैम्बर साहेबान से रिक्वैस्ट करता हूं कि मिनिस्टर साहब जब जवाब दे रहे हों तो बीच में इंट्रप्ट करना शोभा नहीं देता। (शोर)

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी प्रार्थना तो सुन लीजिए।

Mr. Speaker: Swami ji, I will name you. Do not interrupt like this.

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, मैं इंट्रप्ट नहीं कर रहा हूं।

Mr. Speaker: I name Swami Agnivesh.

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, आप मेरा निवेदन तो सुन लीजिए।

कामरेड शंकर लाल: स्पीकर सहाब यह हरियाणा है। यहां की भाशा हिन्दी है। यह इंग्लैंड और अमेरिका नहीं है कि यहां अंग्रेजी बोली जाए। (शोर) यहां हिन्दी में बोला जाना चाहिए। (विघ्न एवं शोर)

स्वामी आदित्यवेश: मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप हमारे ऊपर अंग्रेजी न थोपें। (शोर)

Mr. Speaker: Swami ji, please withdraw from the House.

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिए।

(इस समय सारजैंट एट आर्मज स्वामी अग्निवेश जी की सीट पर गए और स्वामी अग्निवेश जी सदन से बाहर चले गए) (शोर)

श्री अध्यक्ष: इस हाउस में जो भी बात होगी वह मेरे से मुखातिब होकर कही जाएगी।

कामरेड शंकर लाल: मैं स्पीकर महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यहां हिन्दी में बोला जाए।

Mr. Speaker: Hon'ble Minister may please continue.

Sh. Verender Singh: Action according to the recommendations of the Committee and decision of the Govt. thereon has been completed on 21 reports, 6 reports have been returned to the Committee for further investigation, 67 reports have been forwarded to the concerned departments for necessary action and the remaining 24 reports are under consideration fo the Vigilance Department. (Interruptions)

(d) Yes. 2 complaints against 2 M.Ps. and 28 complaints against 14 M.L.As. have been received. Complaints against Ministers are not in the purview of the Committee.

(e) 6 complaints have been filed by the Committee after investigation and 24 complaints are under investigation.

(f) (i) T.A./D.A. has been paid to each Member as under:

1.	Pt. Sh. Ram Sharma Chairman/Single Member	4020.90
2.	Sh. Rrij Mohan Gupta, MLA, Member	916.60
3.	Sh. Harswarup, MLA, Member	3185.10

4.	Rao Ram Narian, MLA, Member	4104.70
	Total	12227.30

(ii) A sum of Rs. 88604.20 has been spent on the maintenance of official car provided to the Committee.

राव राम नारायण: इस कमेटी ने गवर्नमैंट को जो रिकोमैंडेशंज भेजी हैं उनमें से क्या किसी केस में किसी को सजा भी हुई है?

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल): यह इस वक्त बताना पब्लिक इंट्रैस्ट में नहीं है।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, यही पंडित श्री राम शर्मा प्रताप सिंह कैरों के टाईम में भी विजिलैंस कमेटी के चेयरमैन थे। बाद में जो दूसरी सरकारें आई उनमे भी यही विजिलैंस कमेटी के चेयरमैंन थे। अब भी दो तीन बार यही चेयरमैन बने हैं। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि इन्हीं को ही क्यों चेयरमैन बनाया जाता है और इनकी रिपोर्ट पर गौर भी किया जाता है या नहीं?

चौ. देवी लाल: स्पीकर साहब, यह कमेटी इसलिए बनाई जाया करती है कि गवर्नमैंअ पोलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज और एक्शन्ज की बाबत वैल इन्फार्मड रहे। यही वजह थी कि सरदार प्रताप सिंह कैरों ने इनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया था और यही वजह है कि मैंने भी इनको ही इस कमेटी का

चेयरमैन बनाया है। यह पब्लिकइन्ट्रैस्ट में नहीं है कि सारी चीजें हाउस में बताई जाएं।

श्री शमशेर सिंह: क्या मुख्य मंजी जी बताएंगे कि किन दो एम.पीज. और 14 एम.एल.एज. के खिलाफ रिपोर्ट आई है?

चौ. देवी लाल: यह कमेटी सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि गवर्नमैंट वैल इन्फार्मड रह नाम बताना पब्लिक इंट्रैस्ट में नहीं है।

श्री शमशेर सिंह: स्पीकर साहब, यह पब्लिक इंट्रैस्ट के खिलाफ कैसे है जबकि इन्होंने स्वयं बाताया है कि दो एम.पीज. और 14 एम.एल.एज. के खिलाफ शिकायत आई है। यह पता लगना चाहिए कि वे एम.पीज. और एम.एल.एज. कौन से हैं?

Mr. Speaker: That is up to the Government to judge what is in the public interest and what is not. इन्होंने नम्बर रिवील कर दिया, यही काफी है। जिसके खिलाफ शिकायत जेरे गौर है उनके नाम बताना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, मैं सिंचाई ओर बिजली मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या उनको केवल वर्जड ही अंग्रेजी में पढ़ने आते हैं, फिगर्ज नहीं? एक तरफ तो हिन्दी के लिए इतना बोलबाला है लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजी पढ़ते हुए चार हजार एक सौ चार और तीन हजार एक सौ तीन कहा जाता है। फिगर्ज भी तो अंग्रेजी में पढ़ी जानी चाहिए थीं। यह तो

नहीं होना चाहिए कि वर्डज के ऊपर अंग्रेजी और फिगर्ज के ऊपर हिन्दी। यह चुआयस का सवाल नहीं है। फिगर्ज के लिए भी फोर थाउजैंड वन इन्डर्ड एंड फोर कहा जाता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हम बड़े आराम से हिन्दी बोलना चाहते थे लेकिन अगर ऐसा करने के लिए हमें जबरदस्ती फोर्स किया जाएगा तब तो हम मजबूर नहीं होंगे क्यौंकि हाउस के अन्दर दोनों भाशाएं बोली जा सकती हैं और मेरी मर्जी है चाहे मैं जैसे बोलूं।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: मैं इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि इस कमेटी में किस क्राईटेरिया के तहत यह रखा गया है कि एम.एल.एज. के खिलाफ तो शिकायतें सुनी जाती हैं लेकिन मंत्रियों के खिलाफ नहीं? जब मंत्री जी एम.एल.एज. में से बनते हैं तो क्या वजह है कि मंत्रियों को इसके परव्यू से बाहर रखा गया है?

चौ. देवी लाल: इसकी वजह मैंने पहले ही कह दी है कि गवर्नमैंट सारे एम.एल.एज. की ऐक्टिविटीज के बारे में वैल इन्फामर्ड रहे इसलिए यह कमेटी बनाई गई है। जहां तक मिनिस्टर्ज की ऐक्टिविटीज का ताल्लुक है उनसे चीफ मिनिस्टर हर वक्त वाकिफ रहता है।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी बताया कि 21 केसिज में कार्यवाही मुकम्मल हो चुकी है लेकिन

उनके नाम नहीं बताए जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि इसका फिर क्या फायदा हुआ जब इससे यही पता न लगे कि किसके खिलाफ क्या बात है?

10.00 बजे

श्री अध्यक्ष: पब्लिक इन्ट्रैस्ट के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब पहले ही कह चुके हैं। मैं आपके सामने एक प्रसिडैट रखना चाहता हूं (विघ्न) The chair understands what is "public interest". It is a well-known phrase. But whether a particular matter is or is not in public interest is entirely for the Government to decide and judge. यानी यह गवर्नमैंट को अख्तियार है कि वह फैसला करे कि क्या चीज पब्लिक इन्ट्रैस्ट में है और क्या चीज पब्लिक इन्ट्रैस्ट में नहीं है।

चौ. देवी लाल: उसको गवर्नमैंट ने सोच–समझ कर बनाया है। जिस किस्म की इन्फर्मेशन गवर्नमैंट को चाहिए इसकी रिपोर्ट से लेती है। जहां एक्शन लेना हो वहां एक्शन ले सकते हैं।

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, इस कमेटी के चेयरमैन जिस मकान में रहते हैं वह कांग्रेस पार्टी का है यानी कांग्रेस भवन के नाम से है तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि जो आदमी खुद भ्रश्ट हो वह दूसरों की क्या चौकसी करेगा?

चौ. देवी लाल: यह बिल्कुल गलत इल्जाम है। उन दिनों जब यह कांग्रेस कमेटी का दफ्तर हुआ करता था उस वक्त इसकी पहले ही पूरी इन्क्वायरी हो चुकी है। अब यह मामला यहां पर उठाना उचित नहीं।

चौ. हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस कमेटी के चेयरमैन एक महीने में कितने दिन टूर कर सकते हैं और टूर के बारे में क्या कुछ हिदायते दी गई हैं?

चौ. देवी लाल: कोई खास हिदायतें नहीं हैं। अमूमन वे अपनी सहलियत के मुतालिक प्रोग्राम बनाते हैं।

श्रीमती शान्ति देवी: स्पीकर साहब, एक इतनी इम्पोर्टेन्ट कमेटी है और उसके चेयरमैन पर सदन के अन्दर एक माननीय सदस्य ने खुलें आरोप लगाये हैं, क्या उन्होंने यह जिम्मेदारान बात की है? क्या इस बारे में जांच के लिए कोई कमेटी नियुक्त करेंगे?

श्री अध्यक्ष: मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि यह आरोप सरासर गलत है।

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं इस बात को सावित करूंगा। उस मकान के लिए हमने खुद चन्दा दिया था। श्रीराम शर्मा ने नाजायज कब्जा यिका हुआ है।

श्रीमती शान्ति देवी: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से फिर अनुरोध करूंगी कि सदन की भावनाओं का ख्याल रखते हुए चौकसी कमेटी के चेयरमैन पर जो आरोप लगाये हैं उसके बारे में कमेटी मुकरिर की जानी चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछने का टाईम है। आप सवाल पूछिए।

चौ. देवी लाल: यह क्वैश्चन आवर है। जो क्वैश्चन किया गया है उसये यह सवाल ही पैदा नहीं होता है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री भले राम: क्या चीफ मिनिस्टर साहब बतायेगें कि जिन 14 एम.एल.एज. के खिलाफ दरखास्तें आई हैं उनमें कुछ अपोजीशन के भी हैं या सभी जनता पार्टी के है?

चौ. देवी लाल: इसमें जनता पार्टी के ही नहीं बल्कि सात अपोजीशन के भी हैं।

श्री जयनारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रश्नोतर काल है लेकिन मैं भाशा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछने के अलावा इस समय और कुछ नहीं कहा जाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह: क्या मुख्ममंत्री जी बतायेंगे कि इस कमेटी की फंक्शनिंग पर टोटल कितना खर्च हो चुका है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: सवाल के जवाब में सारा खर्चा बताया जा चुका है कि कितना टी.ए. का और कितना दूसरा खर्चा हुआ है।

चौ. पीर चन्द: स्पीकर साहब, यह कमेटी भ्रश्टाचार की छान–बीन के लिए बनाई गर्ठ है। इस कमेटी ने पीछै भी इन्कवारी की है और मौजूदा साल में भी इन्कवारी की है तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि इस साल में कितने एम. पीज. और एम.एल.एज. के बारे में शिकायतें आई हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: इसका जवाब पहले ही दे दिया है। इस सरकार के आने के बाद यह कमेटी बनाई गई है। एम.पीज. और एम.एल.एज. का नम्बर भर दे दिया है।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जो विजिलैन्स कमेटी बनी हुई है उसके चेयरमैन ने जो डिस्ट्रिक्ट लैवल पर चेयरमैन बनाये हुए हैं उनके खिलाफ लड़कों ने नारे लगाये थे और वे गिरफतार भी हुए थे, क्या लडके कालेज मैं है?

श्री अध्यक्ष: अगर आप इसका अलग से नोटिस देंगे तो जरूर जवाब देंगे।

लाला बलवन्त राय तायल: क्या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे की जो एम.एल.एज. और एम.पीज. के लिए विजिलैन्स कमेटी बनाई

है क्या इसी प्रकार से हाई–अपस के लिए लोकपाल नियुक्त करने का विचार है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह पालिसी मैटर है। जब सरकार ठीक समझेगी तो लोकपाल बिल ले आयेगी।

चौ. संत कंवर: क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि इस कमेटी के चैयरमैन ने पिछले दिनों चुनाव के दौरान कुछ एम.एल.एज. के हल्कों में विरोध में खुले आज जलसे किये थे। अब वे उन एम.एल.एल. के हल्कों के सरपंचों और दूसरे आदमियों के खिलाफ दरखास्तें लेकर उनको तंग करते हैं। उनको तंग करके अपने 'हरियाणा तिलक' अखबार का मेम्बर बनाते जा रहे हैं?

चौ. देवी लाल: सरकार कमेटी बनाते वक्त कोई ऐसी पाबन्दी नहीं लगाती कि किसने पार्टी की मदद की और किसने मुखालफत की है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि एम.एल.एज. और एम.पीज. के नाम यहां पर बताना पब्लिक इन्ट्रैस्ट में नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूं कि क्या वे शिकायत सिद्ध होने के बाद उन मैम्बरान के नाम डिस्कलोज करेंगे या नहीं?

चौ. देवी लाल: यह गवर्नमैंट डिसाइड करेंगी कि उन शिकायतों की बिनाह पर क्या एक्शन लेना चाहिए, नाम डिस्कलोज नहीं करेंगे।

कामरेड शंकर लाल: स्पीकर साहब, जिस कमेटी के चेयरमैन श्रीराम शर्मा बनाये हुए हैं क्या उन्होंने हरियाणा में जाकर इस किस्म के केस की सुनवाई की है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि एक मैम्बर के अलावा दूसरा मैम्बर इस कमेटी का क्यों नहीं है?

चौ. देवी लाल: यह पालिसी मैटर के तौर पर है। इसका चौकसी कमेटी इसीलिए नाम रखा है ताकि सरकार पर चौकसी रहे। ज्यादा मैम्बर होने की वजह से कुछ बातें निकलने का डर था इसलिए एक मैम्बर कमेटी बनाई है।

Per Child Average Annual Expenditure on Providiing Education

***1128. # Swami Agnivesh**: Will the Minister for Education be pleased to state –

a) the per child average annual expenditure being incurred by the

#Put the Sh. Jai Narain Verma on his behalf.

Government on providing education and other facilities to children of Moti Lal Nehru Sports School and Kamla Nehru School;

b) the per child average annual expenditure being incurred by the State Government on providing education and other facilities in Primary Schools being run in villages; and

c) whether there is any proposal under consideration of the Government to close all the Public Schools running in the State?

Education Minister (Sh. Hira Nand Arya):

(a) Moti Lal Nehru School of Sports (1976-77).....

(इस समय बहुत से मैम्बर बोलने के लिए खड़े हुए) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज आप लोग बैठ जाएं (व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सवाल न. 1128 का जवाब अगर हो सकता है तो हिन्दी में दे दिया जाए।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितना प्यार हिन्दी से दूसरे मैम्बर्ज को है उतना ही प्यार हमको है लेकिन अगर किसी को हिन्दी का फोबिया हो तो उससे काम नहीं चलेगा। मेरी प्रार्थना है कि अगर सिकी को भी हिन्दी में बोलने के लिए मजबूर न किया जाए तो यह अच्छी बात होगी। (व्यवधान)

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। इनका यह कहना कि जानबूझ कर हिन्दी थोपी जा रही है, बिल्कुल गलत हैं इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

अध्यक्ष द्वारा रूलिंग

सदन में भाशा के प्रयोग संबंधी

श्री अध्यक्ष: देखिए मैम्बर साहिबान, जो लैग्विज का सवाल है इसके बारे में मैं एक दफा पहले बहुत डिटेल्ड रूलिंग दे चुका हूं और मैं आप लोगों के सामने फिर पढ़ना चाहता हूं। The question of use of language in the Assembly, यानी असैम्बली के अन्दर क्या भाशा इस्तेमाल की जाएगी यह सवाल काफी दफा रेज हो चुका है, कई मैम्बर साहिबान ने रेज किया है। I regret to say that this point has been agitated time and again by the members without proper appreciation of the Rules of Procedure. I would invite the attention of the hon. Members to Rules 77 of our Rules of Procedure which reads as under –

> "Subject to the provisions of Article 210 of the Constitution, the proceedings in eh Assembly shall be conducted in Hindi or in Punjabi or in the English languages".

Even according to Article 210 of the Constitution, the business in the legislature of a State shall be transacted in the official language or languages of the State or in Hindi or in

English. Besides, according to section 5 of the Haryana Official Language Act, 1969, unless and until the State Government otherwise directs by notification, the English language may, as from the appointed day, continue to be used, in addition to Hindi, for the transaction of business in the legislative of the State.

It will thus be seen that according to the aforesaid provisions, the proceedings in the Assembly shall be conducted in Hindi or in Punjabi or in English and as such it is apparent that all the three languages can be used for transaction of proceedings in this House. लेकिन मैं हाउस को अश्योर करना चाहता हूं कि हिन्दी को ऐनकरेज ओर प्रोमोट करने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और शायद मैम्बर साहेबान ने यह नोटिस लिया होगा कि हरेक रूलिंग, या जो मोशंज पर वोटिंग का मामला होता है वह मैं हिन्दी में कंडक्ट कर रहा हू लेकिन जो शिक्षा मंत्री ने प्वाएंट रेज किया है, मैं शिक्षा मंत्री के प्वाएंट से सौ फीसदी सहमत हूं कि अगर किसी चीज को प्रोत्साहन देना है तो आहिस्ता–आहिस्ता अपने दिल और अपने दिमांग से दिया जाता है। अगर कोई चीज किसी के ऊपर ठोंसी जाती है तो उसकी अपोजीशन पैदा होती है। जो मैम्बर ऐसा करते हैं वे उसकी डिससर्विस कर रहे हैं, उसकी सर्विस नहीं कर रहे हैं। मैं सब से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि हिन्दी के प्रयोग में वे पूरा सहयोग दें और हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मेहरबानी करके इसको किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करने के बारे में न सोचें। इससे हाउस का वक्त जाया

होता है। बहुत से मैम्बर साहेबान बोलना चाहते हैं लेकिन इसी चीज में हाउस का समय जाया हो रहा है। इसके लिए में आप सब का सहयोग चाहूंगा और मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप इसमें मेरी मदद करें।

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौ. भजन लाल): स्पीकर साहब, हरियाणा प्रान्त हिन्दी भाशी प्रान्त हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब मन्त्रियों को यह कहें कि जब वे हिन्दी बोल सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हिन्दी का प्रयोग करें।

श्री अध्यक्ष: यह मैंने पहले ही कह रखा है।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी बाहर चले गए थे मैं आप से प्रार्थना करना चाहूंगा कि सेक्रेटरी साहब को भेजकर स्वामी जी को बुला लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी को मेरी तरफ से रिक्वैस्ट कर दें कि वे बड़ी खुशी से अन्दर आ जाएं। अब मंत्री जी सवाल नम्बर 1128 का जवाब दैगें। (व्यवधान)

चौ. शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, आपने जो पढ़कर सुनाया है उससे हम सहमत हैं। अगर किसी को हिन्दी बोलने में मुश्किल पेश आ रही हो तब तो ठीक है लेकिन मंत्री जी तो रोज हिन्दी बोलते रहे हैं। ये रात–रात में अंग्रेजी कहां से पढ़कर आ गए हैं। इन्होंने यह जिद्द क्यों पकड़ी है कि हिन्दी नहीं बोलनी

है। मंत्री जी की तरफ से जिद्द है मैम्बरों की तरफ से जिद्द नहीं है (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: बात तो केवल इतनी है कि किसी पर कोई भाशा थोपनी नहीं चाहिए। अब आप लोग बैठ जाएं। अब लैग्विज वाला क्वैश्चन क्लोज होता है क्वैश्चन आवर में दस मिनट बाकी हैं। मंत्री जी अपना जवाब पढ़ें।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री हीरा नन्द आर्य:

(क)	(1)	मोती लाल नेहरू स्कूल आफ स्पोर्टस (1976–77)	रूपये 4613.15
	(2)	कमला नेहरू स्कूल आफ स्पोर्टस (1976–77)	रूपये 3162.87
(ख)		वर्श 1976–77 के दौरान	रूपये 118.37
(ग)		जी नहीं	

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने अपने जववाब में कहा कि कि मोतीलाल नेहरू स्कूल आफ स्पोर्टस में एक लड़के के उपर 4,613.15 रूपये खर्च आया है

और कमला नेहरू आफर स्पोर्टस में एक लड़के के ऊपर 3162.87 रूपये खर्च आया है और गांवों में एक लड़के के ऊपर केवल 118. 37 रूपये खर्च आया है। एक तरफ तो सरकार गांवों और शहरों की बात करती है और दूसरी तरफ इतनी डिसपैरिटी क्यों है? दूसरी पब्लिक स्कूलों के बारे में कहा गया है कि अीाी उन्हें बन्द करने का सरकार का कोई विचार नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस पर विचार करने की आवश्यकता क्यों महसूस नहीं की जा रही है?

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैम्बर साहब को यह बताना चाहता हूं कि इस समय ऐसी कोई प्रोपोजल सरकार के विचारधीन नहीं है। अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी तो फिर इस पर विचार किया जाएगा।

चौ. देस राज: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में पार्ट 'ग' के उत्तर में बताया है कि 'जी नहीं'। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या और पब्लिक स्कूल खोलने की सरकार की कोई प्रोवीजन है?

श्री हीरानन्द आर्य: इस समय सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर साहब ने अपने उत्तर में बताया है कि आफ स्पोर्टस में एक मोती लाल नेहरू स्कूल आफ स्पोर्टस में एक लड़के पर 4613.15 रूपये, कमला नेहरू

स्कूल लड़के पर 3162.87 रूपये और गांवों में एक लड़के के ऊपर 118.37 रूपये खर्च आता है। राई के स्कूल पर 80 परसेन्ट ढटेट का पैसा खर्च हो रहा है और तक वहां से एक भी राश्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनकर नहीं निकला है। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब ऐसी हालत है तो फिर यह सारे का सारा पैस इस स्कूल पर खर्च करने की बजाये सारी स्टेट के स्कूलों के अन्दर क्यों नहीं बांट दिया जाता? क्या सरकार का ऐसा करने का कोई विचार है?

श्री हीरानन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आनरेबल मैम्बर को यह बताना चाहता हूं कि यह स्कूल 1937–74 में स्थापित हुआ था और इस थोड़े समय के आधार पर यह कह देना कि इस स्कूल से अभी तक राश्ट्रीय स्तर का एक भी खिलाड़ी नहीं पैदा हुआ है या राश्ट्रीय स्तर पर किसी खिलाड़ी की कामयाबी नहीं मिली है, एक इममैच्योर सी बात होगी।

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं। (शोर)

श्री अध्यख: स्वामी जी, मैंने समय पर आपको बोलने का पूरा मौका दिया है और आप बार–बार रूलिंग के बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता।

Supply of liveies to class IV in the State

***1172. Comrade Shankar Lal**: Will the Minister for Health be pleased to state whtehr all regular class IV employees ini all the Government Department in the state are being supplied liveries in implementation of the announcement made by the Haryana Government in 1974; if not the reasons therefor?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डा. कमला शर्मा):

पहला भाग: जी हां

दूसरा भाग: प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Purchase of new Buses

***1109. Sh. Jai Narain**: Will the Chief Ministe be pleased to state the total number of new buses p9urchased and allotted to the deports/sub-depots separately during the current financial year in the State?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला): कथन सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरणिका

क्रमांक डिपोज को अलाट की गई बसें		डिपुओं के सब–डिपुओं

					को अलाट की गई बसें
1	अम्बाला	62	1	नारायणगढ़	3
2	चण्डीगढ़	36		यमुनानगर	3
3	करनाल	29		कालका	2
4	जींद	19		दिल्ली	20
5	गुड़गांव	76		पलवल	10
6	रोहतक			फरीदाबाद	7
7	हिसार			गोहाना	7
8	रिवाडी			सोनीपत	4
9	भिवानी			झज्जर	7
10	सिरसा			हांसी	5
11	कैथल			टोहाना	5
	कुल	512		दादरी	6
				लोहारू	2

				डबवाली	5
					80

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं चीफ पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो नई बसें ली गई हैं, उन में से फलीअ में कितनी बसों की एडीशन की गई है और पुरानी बसों को कितनी नई बसों से रिप्लेस किया गया है?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, अभी मैं डिपो वाईज नहीं बता सकता कि एक–एक डिपो में कितनी कितनी नई बसें दी गई हैं। टोटल 275 बसें आई थीं, उनमें से 75 बसें हमारे फलीट में एड हुई है। उसके बाद 153 बसें और आई जिनमें से 82 हमारे फलीट में एड हुई। जो बसें उसके बाद में आई उनकी संख्या है 277, उनमें से 222 बसें रिप्लेसमेन्ट में गई और 55 फलीट में एड हुई।

श्री शमशेर सिंह: स्पीकर साहब, क्या चीफ पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी साहब बताएंगे कि जीन्द डिपो और नरवाना सब डिपो में कितनी कितनी नई बसें दी गई हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैम्बर की जानकारी के लिए बता देता हूं कि जींद डिपो को 19 नई बसें दी गई हैं। जहां तक नरवाना सब–डिपो को बसिज देने

का सवाल है इसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि हम तो डिपो वाईज बसें अलाट कर देते हैं, आगे अब डिपो वाईज अलाटमेंट उनकी अपनी मर्जी पर होती है।

श्री लहरी सिंह मेहरा: स्पीकर साहब, सब से पहले हम डिपोज को रिप्लेसमेंट की बसें देते हैं यानी कडैम्ड बसों के बदले नई बसें देते हैं और उसके बाद नई बसें डिपो वाईज अलाट कर दी जाती हैं।

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, पिछली दफा यह बताया गया था कि हम हरियाणा के अन्दर बसों की बाडी बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे जिस पर 10 लाख रूपये खर्च आने का अन्दाजा था। क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, हमने हरियाणा में कुछेक बसें बनाने का कार्य शुरू कर दिया है और हमारा ख्याल है कि हम भविश्य में भी अपनी ही वर्क शापस में इस कार्य को करेंगे।

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा चीफ पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस सरकार का राज था उस समय संजय गांधी की फर्म ने जो बसिज की बाडीज बनाई थीं, वे गारन्अी पीरियड से पहले ही टूट चुकी हैं। क्या सरकार इस केस की इंकवायरी करवाएगी कि ऐसा कैसे हुआ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौ. ईश्वर सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि कैथल डिपो में कितनी नई बसें दी गई हैं? अगर नहीं, तो इस डिपो की पतली हालत को देखते हुए सरकार यहां पर नई बसें भेजने का कश्ट करेगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, कैथल डिपों को 37 बसें दी गई हैं।

डा. बृज मोहन गुप्ता: स्पीकर साहब, अभी चीफ पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी साहब ने बताया कि बाडी बिल्डिंग का काम हरियाणा में शुरू कर दिया है। क्या चीफ पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी महोदय बतायेंगे कि यह काम किस जगह पर और किस माध्यम से शुरू किया गया है?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, गुड़गांव डिपे के अन्दर कुछ बसों की बाडीज बनी हैं और जो एक्सीडेन्ट होने के कारण बाडीज टूट जाती हैं वह भी हम तकरीबन हरेक डिपों में एक–एक, दो–दो बाडीज बना चुके हैं।

चौ. लाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से चीफ पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जो पैसेन्जर पैसा देकर गाड़ी में सफर करते हैं, खराब बसें होने के कारण उनको परेशानी होती है। सरकार ने कालका और नारायणगढ़ के हल्के में जो पीपों के ऊपर रंग कराकर टूटी–फूटी

बसों का चलन शुरू कर रखा है, वह कब तक बन्द किया जाएगा और उनके स्थान पर कब नई बसें चलाई जाएंगी?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गुजलार सिंह: स्पीकर साहब, 28 फरवरी से आज 22 मार्च का दिन हो गया है, यहां पर हर रोज बसों का कोई न कोई जिक्र जरूर आता है कि हरियाणा में बसों की हालत खराब है। क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि इसमें सुधार लाने की जरूरत है कि नहीं, क्या बसों में सुधार लाया जाएगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, जब से जनता सरकार बनी हैं, हमारे यहां 512 बसें आई हैं। पिछली किसी सरकार के जमाने में इतनी बसें नहीं आई। इस प्रकार लोगों की दिक्कतों को फौरी तौर पर इम्प्रूव करने के लिए पग उठाए जा रहे हैं।

श्री रघुनाथ गोयल: स्पीकर साहब, मैं चीफ पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कैथल में जो नई बसें दी गई हैं, वे कौन–कौन से रूटस पर चलती हैं क्योंकि वहां पर कई ऐसी खराब बसें चलती हैं जिनसे लोगों के कपड़े तक फट जाते हैं। कल मेरा भी कोट एक बस में चढ़ने के वक्त फट गया। क्या सरकार वहां पर इन बसों का रिप्लेसमैन्ट का बन्दोबस्त करेगी?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौ. देस राज: स्पीकर साहब, मैं चीफ पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी साहब से यह जानना चाहता हूं कि करनाल डिपो को कितनी नई बसें दी गई हैं और हरियाणा में कितनी डीलक्स बसें चल रही हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, करनाल में 29 नई बसें दी गई हैं। डीलक्स बसों के बारे में कि इस वक्त कितनी हरियाणा में चलाई जा रही हैं, इस वक्त यह फिग्गर मेरे पास नहीं है? करनाल डिपो हमारे अच्छे डिपोज में से एक है।

कंवर रामपाल सिंह: स्पीकर साहब, अभी चीफ पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी साहब ने बताया है कि करनाल डिपो सबसे अच्छा डिपो बनाया गया हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि करनाल डिपो में कितनी बसें रिप्लेस की गई हैं और कितनी नई बसें वहां पर जा रही हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, मैंने पहले भी बताया है कि टोटल 29 बसें करनाल डिपो में जा चुकी हैं। जहां तक रिप्लेसमेन्ट का सवाल है, इस बारे में मैं अभी नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष: अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Declaration of Small Scale Industries as sick Industrial Units

***1155. Sh. Fatech Chand Vij**: Will the Minister for Industrial be pleased to state –

(a) whether it is a fact that some Small Scale Industries which were running in loss for the last so many years due to the shortage of electricity supply have been declared as sick units in Haryana State;

(b) if so, the district-wise detail thereof;

(c) whether the Government has made any scheme for enabling them to start working again; and

(d) if so, the nature thereof?

उद्योग मंत्री (डा. मंगल सैन):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग)	एक राज्य स्तर तालमेल कमेटी बिमार तथा बन्द लघु
तथा	उद्योग इकाइयों को दोबारा चालू करने के लिये बनाई

(घ)	गई है।

Committee constituted to consider the demands of work-charged employees

***1165. Rao Dalip Singh**: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state –

(a) whether it is a fact that Committee of Administrative Secretaries/Engineer-in-Chief was constituted in the year 1978 to consider the demands of work-charged employees in Irrigation Department;

(b) if so, the recommendations, if any, made be placed on the Table of the House; and

(c) the details of recommendations which have been accepted by the Government so far?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(ए) प्रमुख अभियन्ताओं अथवा प्रशासकीय सचिवों की किसी कमेटी का गठन नहीं किया गया था। यद्यपि इस मामले पर प्रशासकीय सचिवों तथा लोक निर्माण विभागों के प्रमुख अभियन्ताओं द्वारा दो बैठकों में विचार–विमर्श किया गया था।

(बी) वर्क–चार्जड कर्मचारियों की प्रमुख मांगें निम्नलिखित है:–

(i) वेतनमानों का संशोधन

(ii) तीन/पांच वर्शों के पश्चात उनकी सेवा की नियमित किया जाना।

(iii) मकान किराया भत्ता, साईकल भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा इत्यादि।

(सी) वेतनमानों का संशोधन अनुमोदित हो चुका है। अन्य मांगों पर विचार किया जा रहा है।

Share in the posts of Bhakra Beas Management Board

***918. Swamivditya Vesh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether the State Government has since taken the full share in the posts of the Bhakra Beas Management Board; and

(b) if not, the time by which the full share is likely to be taken?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) नहीं।

(ख) समय की कोई अवधि नियत नहीं की जा सकती है। मामले की भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के साथ पैरवी की जा रही है।

Cases registered agsinst Police Officers

***1105. Rao Ram Narain**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether any cases under the provisions of prevention of Corruption Act were registered agsinst some Gazetted Police Officers in the Haryana State before Janata Party Government assumed office in the State; if so, their number;

(b) whether similar cases have also been registered against Gazetted Police Officers since Janta Party Government came into power in the State; if so, their number;

(c) the number of cases referred to in part (a) and (b) above which have been put up in the Courts for trial; and

(d) the number of such cases which have been withdrawn?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) एक

(ख) कोई नहीं

(ग) शून्य

(घ) शून्य

Revised grades to Beldars

***1129. Swami Agnivesh**: Will the Minister for Public Works be pleased to state –

(a) the reasons for which the revised grades have not been given so far to the employees i.e. Beldars to Foreman working in all Departments of Public Works, which were revised on 1st February, 1969; and

(b) whether the Government will now issue the orders to implement these grades immediately as these were confirmed by the Department is January, 1978 and sanctioned by the Finance Department?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(क) लोक निर्माण विभाग में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को दिनांक 1.2.1969 से संबोधित वेतनमान दिये गये हैं। नियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित

नहीं किए गए थे क्योंकि सरकार ने इनके वेतनमान 1.2.1969 से संशोधित किए जाने बारे में स्वीकृति नहीं दी थी।

(ख) सरकार ने वर्क चार्जड कर्मचारियों के वेतनमान 1.4.1978 से संशोधित किए जाने का निर्णय लिया है।

Regularisation of services of work charged employees

***1173. Sh. Mange Ram Gupta**: Will the Minister for Public Works be pleased to state –

(a) whether it is fact that the Government decided to regulation rise the serivces of work-charged employees of the P.W.D. (Public Health) who had put in five years ro more service;

(b) if so, a copy of the Government's order be laid on the Table of the House;

(c) whether it is also a fact that the Engineer-in-Chief of the P.W.D. (Public Health) asked the Superintending Engineers to send the required information for the implementation of the decision of the Government;

(d) if so, the circle-wise information received be laid on the Table of the House alongwith the number of employees category-wise whose services have been regularized and of those who qualified for being regularized; and

(e) whether there are any persons who fall into the category of work-charged employess as referred to in part (a) above but their services have not been regularized; if so, the reasons therefore and the steps, if any, proposed to be taken to implement the above-mentioned order?

अन्तरिम उत्तर

अ.सं.प. क्र. 17–2–79 लो.नि. 3(1)

''लछमन सिंह

लोक निर्माण मंत्री,

हरियाणा,

चण्डीगढ़।

दिनांक 20.1.79

विशयः तारांकित प्रश्न 1173 जो श्री मांगे राम गुप्ता, विधान सभा सदस्य द्वारा पूछा गया।

प्रिय कर्नल साहब,

उक्त प्रश्न श्री मांगे राम गुप्ता, विधान सभा सदस्य ने पूछा है, जिसकी तिथि 2.3.79 की लगी है। इस प्रश्न के उत्तर के बारे में मैंने यह कहा है कि इसका उत्तर अभी तैयार नहीं है। सदस्य महोदय द्वारा मांगी गई सूचना अधीनस्थ कार्यालयों से एकत्र की जानी है। इसके पश्चात इसे मुख्यालय में कम्पाईल किया

जाना है। सूचना एकत्र करने में कुछ समय लगेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि तारांकित प्रश्न न. 1173 के उत्तर के लिए 22.3.79 की बजाय लगभग 20 दिन के बाद की कोई अन्य तिथि निश्चित करने की कृपा करें।

सादर,

भवदीय,

ह/–

(लछमन सिंह)

कर्नल राम सिंह,

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़।''

Revision of Pay-scales of work-charged employees of P.W.D. (B&R)

***1176. Sh. Shamsher Singh**: Will the Minister for Public Works be pleased to state –

(a) the names of categories of work-charged employees of the P.W.D. (B&R) whose pay-scales were revised in 1969 or subsequently togetherwith the old and revised pay-scales;

(b) whether it is a fact that there are some categories of work-charged employees and regular employees who do the same job and their posts carry different pay-scales;

(c) if so, the pay-sacles for regular and work-charged employees in each category be laid on the Table of the House; and

(d) whether the Government proposes to remove their discrimination in the pay-scales?

Interim Reply

UNO No. 17/3/69-PW III(8)

"Lachhman Singh

Minister

Public Works Department,

Haryana,

Chandigarh.

March, 21st, 1979.

Sub: Starred Question NKo. 1176-Sh. Shamsher Singh Surjewala, M.L.A. regarding revision of pay scales of work-charged employees P.W.D. (B&R).

Dear Col. Sabib,

Starred Vidhan Sabha Question No. 1176 is due for answer on 22-3-79. The answer of this question is not ready for want of necessary information from the field offices which is being collected. Some more time is needed for collecting information from field offices and it scompilation. It is, therefore, requested that time limit for answering Starred Assembly Question NKo. 1176 may kindly be extended for above a fornight and some other date may kindly be fixed for its reply.

Yours sincerely,

Sd/-

(Lachhman Singh)

Col. Ram Singh,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Cases of charge-sheet against Officers/Officials

***1060. Sh. Devender Sharma**: Will the Minsiter for Public Works be pleased to state –

(a) whether it is a fact that in a large number of cases charge-sheets against officers/officials in the P.W.D. (B&R) under various rules of the Punishment and Appeals Rules, 1952 have been lying pending with the

Government/E.I.C./S.E.S. for the last more than three years;

(b) whether the responsibility for this delay in the disposal of these cases been fixed, if so, the results thereof;

(c) the time by which these cases are likely to be finalized;

(d) the total amount of money involved in these cases; and

(e) whether any officer/official against whom charge-sheet was pending had retired/died/resigned; if so, the steps taken to safeguard Government interest?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(क) जी नहीं।

(ख)	(ग)	प्रश्न ही पैदा नहीं होता।
(घ)	तथा	
(ङ.)		

Appointment of Tehsildars

***1038. Dr. Brij Mohan Gupta**: Will the Minsiter for Revenue be pleased to state –

(a) the total number of Tehsildars appointed in Haryana State after the information of Janta Government, upto 31-1-1979; and

(b) the number of Tehsildars out of those referred to in part (a) above who have been appointed through the Subordinate Service Selection Board?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह):

(ए) 12

(बी) तहसीलदारों की नियुक्ति अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल के माध्य से नहीं की जाती अतः संख्या बताने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Shortage of Pucca Bricks

***1103. Ch. Shiv Ram Verma**: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state –

(a) whether the Government is aware of the fact that there is great shortage of “pucca” bricks in the State; and

(b) if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government to remove this shortage of "pucca" bricks?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौ. गजराज बहादुर नागर):

(अ) हां, राज्य के कुछ भागों में पक्की ईटों की कमी है।

(ब) ईटों की कमी कोयले की कम सप्लाई के कारण हैं। राज्य में कोयले का अधिक आयात करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Pay-scale of Yoga Instructors

***1168. Sh. Mool Chand Mangla**: Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give the Pay-scale of Rs. 300-600 for the posts of Yoga Instructors only to those persons who do diploma in Yoga of One-year duration from Lonawala?

शिक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य): नहीं।

Model Villages Scheme in the State

***1154. Smt. Sushma Swaraj**: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state –

(a) the number of villages in the State which have been included in the Model Villages Scheme;

(b) the district-wise names of the said villages; and

(c) the criteria adopted for the inclusion of villages in the said scheme?

विकास मंत्री (ठाकुर बीर सिंह):

(ए) कुल 5 आदर्श ग्राम।

(बी)	आदर्श ग्रामों का नाम	जिला
1	अर्जाहेड़ी	करनाल
2	मन्धोर	अम्बाला
3	खनक	भिवानी
4	फिरोजपुर नमक	गुडगांवा
5	आजाद नगर	रोहतक

(सी) आदर्श ग्रामों के चुनाव के लिए कोई निर्धारित क्राईटेरिया नहीं था। भूतपूर्व अध्यक्ष, ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा

सिफारिश किये गये 8 ग्रामों से उक्त 5 आदर्श ग्राम ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा चुने गये थे।

आदर्श ग्राम योजना समाप्त कर दी गई है तथा अब केवल फोकल ग्राम ही चुने जाते हैं। फोकल ग्रामों को चुनने के लिए जो तरीका अपनाया गया है, वह यह है कि प्रत्येक उपायुक्त को सम्बंधित जिले के 2 या 3 गावों के बारे में उनके अन्दर जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, की जानकारी देने को कहा जाता है। इन गांवों के पास 25–30 एकड़ शामलात भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। इस जानकारी के आधार पर ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा फोकल ग्राम का अन्तिम चुनाव किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: साहेबान, कल सुबह साढ़े ग्यारह बजे बिजनैस एडवाजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें ये फैसले किये गये .....

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं कि परसों मैंने एक काल अटैन्शन मोशन दिया था.....(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, जब मैं बोल रहा हूं तो बीय में इन्ट्रप्ट करना ठीक नहीं है, आप मुझे हमेशा बीच में इन्ट्रप्ट करते हैं, ऐसा करना उचित नहीं है।

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, यह जीरो आबर है . .....(शोर)

श्री अध्यक्ष: जीरो आवर का कोई रूल मेरे सामने नहीं है।

शिक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य): अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी दूसरों को तो हिन्दी में बोलने के लिये कहते हैं लेकिन स्वयं 'जीरो आवर' कह रहे हैं इनको यह भी हिन्दी में कहना चाहिये।

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं कि शराब के नये ठेके नीलाम किये जा रहे हैं जबकि हमारी सरकार की नीति यह हैं कि किसी नई जगह पर शराब का ठेका नीलाम नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में मैंने एक ध्यानाकर्शण प्रस्ताव दिया था लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई .....(शोर)

श्री अध्यक्ष: आपका एक काल अटैंशन मोशन जो बादशाहपुर के बारे में था वह मैंने एडमिट किया था और दूसरा मोशनजो आपने दिया है वह एग्जामिन हो रहा है और उसके ऊपर जल्दी से जल्दी मैं अपना डिसीजन दे दूंगा।

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, जांच पड़ताल होते–होते और नये ठेके नीलाम हो रहे हैं और इससे आमदनी ज्यादा हो रही है .....(शोर)

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, आप जैसे महापुरूश के लिये यह शोभा की बात नहीं है कि आप मुझे बार–बार इन्ट्रप्ट करे। आपका

जो प्रोहिबीशन संबंधी बादशाहपुर के बारे में, काल अटैन्शन मोशन था, वह एडमिट कर लिया गया है। दूसरा जो मोशन आपने दिया वह एग्जामिन हो रहा है। अगर आप यह समझें कि जब तक विधान सभा उसको एग्जामिन करे, सरकार की सारी कार्यवाही बन्द हो जाये, यह नामुमकिन है। गवर्नमैंट अपनी कार्यवाही जारी रखेगी। आपका काल अटैंशन मोशन जैसे मैंने कहा एग्जामिन हो रहा हैं वह कल मिला था और आज मुझे पुट–अप किया गया है जिसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में जाकर डिसीजन लूंगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पेशेंस (धैर्य) रखें। स्वमी में पैशेंस की एक बड़ी क्वालिटी आपकी बात सबसे पहले आए, ऐसा मुनासिब नहीं है। आप धैर्य रखें। आपके काल अटैन्शन मोशन पर जल्दी से जल्दी फैसला होगा।

आचित्य प्रश्न

एडमिट किए हुए ध्यानाकर्शण प्रस्ताव को रिकंसिडर करने सम्बन्धी

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, आपने मेरा काल अटैन्शन मोशन एज न. 23 एडमिट किया था जो आज टेक–अप होना था। थोड़ी देर पहले मुझे आपके दफ्तर से पत्र मिला है कि आप इसको रि–कंसिडर कर रहे हैं। यह मामला बड़ा अरजैट आफ पब्लिक इम्पोर्टैंस का हैं और इसमें ग्रेव इररैगुलैरिटीज का सवाल है .....

श्री अध्यक्षः आपका काल अटैंशन मोशन आया था, मैंने एग्जामिन करने के लिए मैटर गवर्नमैंट को रैफर किया था। गवर्नमैंट का रिप्लाई आ रहा था कि बीच में आप मेरे से फिर मिले थे और आपने मुझे एक चिट्ठी भी दी थी जो मैंने एडमिट की थी। उसके तुरन्त बाद गवर्नमैंट की चिट्ठी आई कि इसको कंसिडर करने के लिए कुछ समय दिया जाए। इसलिए वह क्वैशचन रि–एग्जामिन हो रहा है, वह डिसअलाऊ नहीं हुआ है। जो मैंने रूलिंग दी है अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वह मैंने रूल्ज आफर प्रोसीजर एंड कंडकट आफर बिजनैस के रूल 120 के तहत दी हे जोकि पेज 69 पर है। उसमें स्पीकर की रैजुडियरी पावर्ज का जिक्र है और उसी के तहत मैं यह रि–कंसिडर कर रहा हूं।

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, मैंने क्वैश्चन न. 848 दिया था जिसका 28 दिसम्बर को जवाब मिलना चाहिए था लेकिन गवर्नमैंट ने उसकी एक हफ्ते की एक्सटेंशन मांग ली थी और उसके बाद आपने गवर्नमैंट को रिमाइंडर्ज भी भेजे लेकिन फिर भी उसका जवाब नहीं आ रहा है ....(शोर)

श्री अध्यक्षः जवाब आपको दिखाया जा चुका है लेकिन अगर आप टैक्नीकल प्वांयट लेकर उसको उइाना चाहे तो अलग बात है। (शोर)

श्री कंवल सिंह: इसी तरह से क्वैश्चन न. 159 का भी गल्त जवाब दिया गया है। उसके द्वारा हाउस को डैलिब्रेटली मिसलीड किया गया है। वह पब्लिक इम्पौर्टैंस का मैटर है और चूंकि गल्त जवाब देकर हाउस को मिसलीड किया गया है इसलिए यह मैटर प्रिवलिज कमेटी को रैफर किया जाए। यह सवाल एग्रो इंडस्ट्री में एमरजैंसी के बाद मुलाजिमों की रि–अप्वांयटमैंट और रि–इन्स्टेटमैंट के बारे में था। जिस वक्त मैंने यह सवाल दिया था उस वक्त विजीलैंस की इन्क्वायरी चल रही थी। (शोर)

श्री अध्यक्ष: यह आप नया सवाल उठाना चाहते हैं तो आप मेरे को लिख कर दे दें।

श्री कंवल सिंह: जो कुछ मैंने काल अटैंशन मोशन में दिया है वह मैं पढ़ देता हूं।

Mr. Speaker: Please do not read out the call attention motion. It is not allowed to be read out unless it is admitted.

Sh. Kanwal Singh: I am not trying to read out the whole of it. There are two parts of the motion. One relates to the irregularities and other to giving deliberately wrong replies.

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है कि जो भी ध्यानाकश्रण प्रस्ताव एडमिट किया जाता है उसके लिये कंडीशंज रखी हुई है कि वह पब्लिक

इम्पौर्टैंस का होना चाहिये। अभी इनके मोशन के बारे में आपने कहा कि एग्जामिन करने के लिये सरकार को भेजा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई मैटर अरजैट नेचर का या पब्लिक इम्पौर्टैंस का है या नहीं है इस बारे में स्पीकर साहब को ही फैसला देना चाहिये और सरकार का मश्विरा लेने की जरूरत नहीं है।

Mr. Speaker: I do not agree with you at all. the Speaker can examine a question and take a decision whether in his view it is a matter of urgent public importance or not. According to the Practice and Procedure in Parliament by Kaul and Shakdher, before admitting a motion, the Speaker can call for such information as he considers necessary from the Minister concerned because a notice is inadmissible if it lacks factural basis.

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, जो सवाल मैंने दिया था उसमें बिल्कुल फैक्टस हैं और अगर देखा जाए तो जो गवर्नमैंट का जवाब है उसमें फैक्अस नहीं हैं – (शोर)

श्री अध्यक्ष: यह तो मेरे को असर्टेन करना हे कि फैक्चुयल पोजिशन क्या है।

श्री कंवर सिंह: अगर आप इजाजत दैं तो मैं फिर डिटेल बना देता हूं –(शोर)

श्री अध्यक्ष: इस वक्त मैं डिटेल्ज आफ केस में जाने के लिये तैयार नहीं हूं I would request the hon. Member to stick to

the rule. I have not yet disallowed your motion. I am only re-examining it. You will agree that I am well within my rights to re-examine the matter.

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है कि जब एक काल अटैन्शन मोशन एडमिट हो चुका है तो उसको रि–कसिंडर करने की क्या जरूरत पड़ गई?

श्री अध्यक्ष: जिस वक्त मैंने वह मोशन एडमिट किया था उस वक्त गवर्नमैंट की रिप्लाई नहीं आई थी लेकिन अब some fresh facts have come to my knowledge. And I am well within my rights to re-examine the matter.

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. राम लाल वधवा): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। पार्लियामैंटरी कनवैंशन यह है कि स्पीकर साहब इन सब बातों का फैसला अपने चैम्बर में बैठकर करते हैं। हाऊस के अन्दर इन बातों पर डिस्कशन या क्वैश्चन नहीं हो सकता हैं। इसलिये मैं रिकवैस्ट करूंगा कि कम से कम स्पीकर की पावर्ज को हाउस में इस तरीके से कवैश्चन करके चैलेन्ज न किया जाये। यदि किसी ने कोई बात कहनी है तो वह आपसे चैम्बर में मिलकर कह सकता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पार्लियामैंटरी कनवैनशंज कायम नहीं रहेंगी।

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं तो केवल इतनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि स्पीकर का जहां तक संबंध है वे हाउस का कोई भी मामला

डिसाइड करने के लिये सामर्थ हैं। जहां तक रूल 120 पावर्ज का संबंध है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। प्रश्न केवल इतना है कि आपने एक मोशन एडमिट कर लिया और उसके बाद सरकार ने किसी कारणवंश कोई फैक्टस दिये जिसकी वजह से मोशन पर रि–कंसिड्रेशन हो रही है। अगर स्पीकर महोदय को अपनी रूलिंग जो उन्होंने पहले, मोशन एडमिट करने की दी, उस पर रिवर्स करने की जरूरत है तो संबन्धित मैम्बर से विचार करना चाहिये ताकि उसके व्यू प्वांयट भी आपके सामने आ सकें।

श्री अध्यक्षः कल जब मेरे पास सरकार से रिप्लाई आया था तो मैंने चौ. कंवल सिंह जी से एम.एल.एज होटल में कंटैक्ट करने की भी कोशिश की, आदमी भी भेजा परन्तु वे उस समय बाहर गए हुए थे मेरी मैम्बर साहेबान से रिकवेस्ट है कि हाउस का समय वेस्ट न करें। (विघ्न) जब मैं बोल रहा हूं तो मैम्बर साहेबान मेरी बात सुनें और मुझे बीच में इंट्रप्ट न करें। जितना वक्त आप इस तरह जाया करेंगे उतना ही हमें बजट पर डिस्कंशन के लिए कम टाईम मिलेगा। चौ. कंवल सिंह जी, आप मेरे से मिल लें, और we can talk it over.

चौ. संत कंवरः प्वायंट आफ आर्डर, सर। मंत्री साहब की और से जब जवाब गलत आया है तो यदि कोई मैम्बर दोबारा उस पर क्वैश्चन रेज करना चाहता है तो उसे करने दिया जाये। सरकार द्वारा कंसिडर करने में इतना समय लगाने पर यह संभावना

लगती है कि चनी के लोग जवाब को ठीक करने के लिए फाईलें बदलने जा रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष: यह प्वायंट आफर आर्डर नहीं हैं। मैं यह कतई कहने को तैयार नहीं कि मंत्री महोदय की ओर से जवाब गलत आया है। लेकिन अगर जवाब गलत आये तो उसका रूल्ज के मुताबिक इलाज किया जा सकता है।

श्री फतेह चन्द विज: प्वायंट आफर आर्डर, सर मेरा क्वैश्चन यह था कि स्टेअ में जो कारखाने बंद पड़े हुए हैं.....

श्री अध्यक्ष: विज साहब, आप बैठ जाइये, यह प्वायंट आफर आर्डर नहीं है।

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब मैं 21 मार्च को कार्य सलाहकार समिति की बैठक में निश्चित हुआ कार्यक्रम पेश करूंगा जो इस प्रकार है:—

समिति ने सिफारिश की कि 22, 23, 26, 27, 28, 29 तथा 20 मार्च, 1979 को सदन द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जायेगा:—

वीरवार, 22 मार्च 1979 को 9.30 बजे प्रातः

1. प्रश्नोत्तर काल।

2. कार्य सलाहकार समिति की तीसरी रिपोर्ट पेश करना तथा ग्रहण करना।

3. वर्श 1979–80 के बजट पर सामान्य चच्रा का पुनरारम्भण तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर।

शुक्रवार, 23 मार्च 1979 को 9.30 बजे प्रातः

1. प्रश्नोत्तर काल।

2. परिवार नियोजन संबंधी सरकारी संकल्प।

3. मांग स. 10–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य।

   मांग स. 15–सिंचाई

   मांग स. 17–कृशि

   मांग स. 18–पशुपालन

   मांग स. 21–सामुदायक विकास

   मांग स. 22–सहकारिता

पर चर्चा तथा मतदान।

शनिवार, 24 मार्च 1979—खाली दिन।

रविवार, 25 मार्च 1979—छुट्टी।

सोमवार, 26 मार्च 1979 को 2.00 बजे मध्याहन पश्चात

1. प्रश्नोत्तर काल।

2. मांग स. 2—सामान्य प्रशासन

मांग स. 3—गृह

मांग स. 9—शिक्षा

मांग स. 12—श्रम तथा रोजगार

मांग स. 16—उद्योग

मांग स. 23—परिवहन

पर चर्चा तथा मतदान।

मंगलवार, 27 मार्च 1979 को 9.30 बजे प्रायः

1. प्रश्नोत्तर काल।

2. वर्श 1979—80 के बजट की शेश मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

बुधवार, 28 मार्च 1979 को 9.30 बजे प्रायः

1. प्रश्नोत्तर काल।

2. (1) बजट के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक, 1979

(2) हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पैन्शन) संशोधन विधेयक, 1979

(3) हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) संशोधन विधेयक, 1979

(4) हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतनमान (संशोधन) विधेयक, 1979

(5) पंजाब कृशि उपज मंडी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1979

वीरवार, 29 मार्च 1979 को 9.30 बजे प्रायः

1. प्रश्नोत्तर काल।

2. गैर–सरकारी कार्य

शुक्रवार, 30 मार्च 1979 को 9.30 बजे प्रायः

1. प्रश्नोत्तर काल।

2. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।

3. सभा के अनिश्चित काल के लिए स्थगित रहने संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।

4. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1979

5. कोई अन्य विधेयक विधान कार्य।

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): मैं प्रस्ताव करता हूं –

> कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन में दी गई सिफारशें स्वीकर करता है।

श्री अध्यक्ष: मैं प्रस्ताव करता हूं –

> कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन में दी गई सिफारशें स्वीकर करता है।

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, आज के लिए जो कार्यवाही निश्चित की गई है उससे यह प्रतीत होता है कि बजट पर बोलने के लिए समय बहुत कम रह गया है क्योंकि वित्त मंत्री महोदय ने भी जवाब देना है और अन्य विधायक भी बोलना चाहते हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि यह तो सदन की बैठक का समय बढ़ा दिया जाये या डबल सिटिंग कर दी जाये।

श्री मूल चन्द जैन: अगर सदन चाहता है कि आज डबल सिंटिग होनी चाहिए तो सरकार को कोई एतराज नहीं है।

Mr. Speaker: Rao Sahib would you like to comment upon it?

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, स्वामी जी ने सुझाव दिया है वह अच्छा है। यह बजट सैशन है और सभी मैम्बरों को ज्यादा से ज्यादा समय मिलना चाहिए यह आपकी इच्छा है कि चाहे इसी सिटिंग का समय बढ़ा दें या दूसरी सिटिंग कर ली जाये।

आवाजें: दूसरी सिटिंग कर ली जाये।

राव बीरेन्द्र सिंह: अगर आपने दूसरी सिटिंग रखनी है तो बेहतर होगा कि इसका समय आज दोपहर बाद 3 बजे से 6 बजे तक का रख दिया जाये और इसमें क्वैश्चन आवर नहीं होगा।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: तो आज हाउस की दूसरी सिटिंग होगी और उसका समय दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा।

उद्योग मंत्री (डा. मंगल सैन): रूल्ज मे मुताबिक इसमें क्वैश्चन आवर नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: हां जी, क्वैश्चन आवर नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन में दी गई सिफारशें स्वीकर करता है।

प्रस्ताव पारित हुआ।

वर्श 1979–80 के बजट पर आम चर्चा पुनरारम्भ

श्री अध्यक्ष: अब साहिबान, साल 1979–80 के बजट पर आम बहस चालू की जायेगी कल जब सदन की बैठक स्थगित हुई थी तो डा. मंगल सैन जी बोल रहे थे, वे अपनी स्पीच जारी कर सकते हैं।

उद्योग मंत्री (डा. मंगल सैन): स्पीकर साहब, कल मैंने अपना भाशण अभी शुरू ही किया था कि हाउस एडजर्न हो गया। स्पीकर साहब, कल मैं यह कह रहा था कि जनता पार्टी ने सता में आते ही एक नारा दिया जिसको पिछली सरकार ने नजरअंदाज कर रखा था। यानी ग्राम विकास, ग्राम में रहने वाले किसान मजदूर, अनुसूचित जाति और पिछड़ी हुई जातियों के लोग या अन्य छोटे व्यवसायों में लगे हुए लोगों का विकास करने के लिये इस सरकार ने बड़ा भरपूर प्रयास किया है। स्पीकर साहब, आपको

मालूम है कि हमारा प्रदेश खेतीहार प्रदेश है लेकिन यहां आबादी ज्यादा है और खेती योग्य जमींन कम है। तो लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए? बेकारी बेरोजगारी और भुखमरी के कारण हरियाणा की जनता परेशान थी उसके लिए हमने यह माध्यम निकाला है कि प्रदेश का तेजी के साथ उदयोगीकरण किया जाए। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि दुनियां में जितने भी देश हैं वे आज बड़े सामर्थ गौरवशाली हैं, स्वावलम्बी हैं और हर लिहाज से मजबूत हैं। वहां इसी के साथ–साथ .....(शोर)

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि रूल 191 में यह है जिसको मैं पढ़ देता हूं। It reads –

"191. (2) The Finance Minister shall have a general right of reply, at the end of the discussion."

तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय एक मैम्बर की हैसियत से बोल रहे हैं या मिनिस्टर की हैसियत से बोल रहे हैं? अगर ये अपने महकमें के बारे में जवाब दे रहे हैं तब तो ये मिनिस्टर की हैसियत से बोल रहे हैं वरना इनको एक मैम्बर की हैसियत से बोलना चाहिए। इसलिए अच्छा यह है कि पहले सब मैम्बर बोल लें और बाद में ये बोल लें।

श्री अध्यक्ष: आप अपना प्वायंट आफर आर्डर कह रहे हैं या सूझाव दे रहे हैं? (शोर) मैं आप से यह पूछ रहा हूं कि क्या आप अपना प्वायंट रेज कर रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं कि मंत्री जी आखिर में बोलें?

श्री जगन नाथ: मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि ये मैम्बर की हैसियत से बोल रहे हैं या मिनिस्टर की हैसियत से बोल रहे हैं?

Mr. Speaker: A Minister can intervene at any time with the permission of the Speaker and I permit Dr. Mangal Sein to speak for a limited period.

Dr. Mangal Sein: For what time?

Mr. Speaker: Say ten/twelve minutes.

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है – (शोर)

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, कल भी जब मैंने बोलना शुरू किया था तो बहिन सुशमा जी एतराज उठाने लगीं। पता नहीं उनको मेरे से क्या कश्ट है? मैं बोल रहा हूं, मैंने अपनी बात कहनी है और मेरे बाद बहिन जी अपनी बात कह लें।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है .....

श्री अध्यक्ष: पहले तो आपने प्वायंट आफर आर्डर श्री जगन नाथ जी के थरू रेज किया था और अब खुद रेज कर रही है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे कश्ट है मुझे कोई कश्ट नहीं हैं। मेरा व्यवस्था

का प्रश्न यह है कि कल आपने नियम 30 के अधीन एक प्रस्ताव पेश किया था जो गैर–सरकारी काम को सरकारी काम में बदलने संबंधी था। वह प्रस्ताव पेश किया था जो गैर–सरकारी काम को सरकार काम मैं बदलने संबंधी था। वह प्रस्ताव सदन ने पास भी किया तो मेरा प्रश्न यह है कि गैर–सरकारी काम का दिन मूलतः सदन के सदस्यों के लिए होता है और उसमें कहीं कोई सरकारी काम नहीं होता। हमने उस दिन को अगर सरकारी काम के लिए बदला था तो महज इस बात के लिऐ मैम्बर्ज को बजट पर बोलने का ज्यादा अवसर प्रदान किया जाए। गैर–सरकारी काम के महत्व को इसलिए छोड़ दिया गया ताकि बजट पर हमें बोलने की अनुमति मिल जाएगी और समय मिल जाएगा हम नहीं चाहते कि उस सारे समय को आप मंत्री महोदयों के वक्तव्यों के लिए छोड़ दें। आप अगर इन्टरवीन करने के लिए कहते हैं तो वह तो अगल बात है लेकिन बेहतर यह है कि .....

Mr. Speaker: This is no point of order.

Smt. Sushma Swaraj: I am still speaking, sir.

Mr. Speaker: I have understood your point. Mrs. Swaraj, you can raise a point of order and not deliver a speech.

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह है कि सब मैम्बरों के विचार सुनकर उसके बाद जो भी मंत्री अपने विभाग के बारे में कहना चाहे कहे।

श्री अध्यक्ष: आपका प्वायंट आफ आर्डर यह है कि मंत्री जी पूरा टाईम ले रहे हैं। मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करता हूं कि वे हाउस का पूरा टाईम कतई न लें। वे केवल 10–15 मिनट में अपनी बात कह दें।

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. राम लाल वधवा): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है कि बहिन जी एक तरफ तो यह कह रही हैं, कि मंत्री जी बाद में बोल लें लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि टाईम तो उतना ही है चाहे वे बाद में बोलें या पहले बोलें।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि आनरेबल मैम्बर को समझा दीजिए कि चेयर की रूलिंग को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। ये बार–बार कह रही हैं कि केवल वित्त मंत्री जी को बाद में बोलने का अधिकार हैं अब स्पीकर साहब, आपने डिसिजन दे दिया है कि That a Minister can invtervene at any stage with the permission of the Speaker. जो स्पीकर साहब, मै तो आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, एक नई प्रैक्टिस शुरू हो रही है। आनरेबल मिनिस्टर इन्टरवीन कर रहे हैं और उनको ट्रैजरी बैचिज की तरफ से ही डिस्ट्रब किया जा रहा है।

Mr. Speaker: It shows the spirit of democracy.

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सहाब, मैं तो कह रहा हूं कि चेयर की तरफ से हर मैम्बर को पूरी प्रोटैक्शन मिलती चाहिए।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं सिर्फ 15 मिनट लूंगा इससे ज्यादा एक मिनट भरी नहीं लूंगा। इस समय 10 बज कर 59 मिनट हुए हैं....

श्री अध्यक्ष: ठीक है डाक्टर साहब, आप बोलिए।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुझे इनकी बात तो समझ में आती है कि मेरे बोलने पर इन्हें एतराज हो सकता है क्योंकि इनको पता है कि मैंने कया बात कहनी है। मुझे यह कहना है कि जो बीमारी, बुराई ये हमारी विरासत में छोड़ गए उस गन्द का बोझा इस डिपार्टमैंट को ढोना पड़ा। स्पीकर साहब, इन्होंने माईनर मिनरल्ज नाम की एक कार्पोरेशन बनाई और महेन्द्रगढ़ जिले में जहां से स्लेट निकलती है वहां पर एक स्लेट हाउस बना हुआ है। उस जगह का इन्होंने कैसे मिसयूज किया और उस समय के मुख्यमंत्री ने अपने इलाके के लोगों को उसमें नाजायज भर्ती किया। कार्पोरेशन पर बर्डन पड़ा और लिहाजा घाटा पड़ा उसको हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और उस काम पर हमने श्री हुक्म सिंह को लगाया है। वे एक निहायत ईमानदार और हमेशा गरीब मजदूर और गरीब किसानों के लिए लड़ने वाले हैं। ऐसे महानुभाव को वहां लगा कर हम उस कार्पोरेशन का काम ठीक कर रहे हैं। इन्होंने तो भट्ठा ही बिठा कर छोड़ दिया था।

इन कांग्रेस वालों की तकलीफ तो मुझे याद आती हैं कि यह उस फलैट हाउस में क्या किया करते थे वह कहानी मैं नहीं कहना चाहता। इसी प्रकार से इन्होंने एक टेलीविजन नाम की एक कम्पनी फरीदाबाद में खोल दी। उसके भूतपूर्व मैंनेजिंग डायरैक्टर पर एक केस फाईल किया हुआ है। स्पीकर साहब, मैं विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मामला सब–जुडिस है। इसी प्रकार से इन्होंने हरियाणा पोलिस्टील नाम की एक कम्पनी हिसार में बनाई उसमें करोड़ौं रूपए का घाटा हो गया। उस समय के हाकिमों ने वहां ऐसी साजबाज की थी जिसको हमने ठीक करने की कोशिश की। उस काम को ठीक करने के लिए हमने पिछले दिनों एक आदमी लगाया था। हमने देखा कि यह आदमी ठीक काम नहीं करेगा इसलिए हमने उस आदमी को भी निकाल दिया। उस कम्पनी का आडिट करवा कर मैंने उस केस को विजीलैंस को दे दिया। स्पीकर सहाब, गल्त काम के खिलाफ केस बनाने की इनकी कभी जुरर्त नहीं पड़ती थी इसलिए अब इनको तकलीफ हुई। स्पीकर सहाब, 1977 में भिवानी की एक फर्म से गलत आंकड़े ले करके इन्होंने उसको सबसिडी देने का प्रोग्राम बनाया। वह ऐसा चालाक आदमी था कि जून के महीने में ही पैसे निकलवा कर ले गया। उसने मंजूरी इनके वक्त में ली थी और पैसे इस गवर्नमैंट के वक्त में निकलवा लिये। मैंने उस आदमी को और जो संबंधित अफसरान थे उन सबाके विजीलैंस को सुपुर्द कर दिया। मैंने कहा कि मैं इस राज्य में भ्रश्टाचार नहीं चलने दूंगा। स्पीकर साहब, जितनी कार्पोरेशन्ज आज हमारे पास हैं, इनमें से ब्रियूरीज

कार्पोरेशन को छोड़ कर, चाहे फाईनेन्शियल कार्पोरेशन है, इडंस्ट्रियल डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन है या स्माल स्केल इडंस्ट्रीज एंड एक्सपोर्टस कार्पोरेशन है सब बहुत टोटे में है। इनके वक्त में क्या होता रहा? उस स्माल स्केल इडंस्ट्रीज और एक्सपोर्ट कार्पोरेशन का चेयरमैन वर्ल्ड के टूर करता फिरा और लाखों रूप्ए का बोझ इस कार्पोरेशन पर पड़ा। तब की टूटी हुई कमर को हम सीधा करना चाहते हैं जो नहीं होती है। इनके समय में इतना नुकसान हुआ है। अब अपोजीशन में बैठ करके मेरे भाई मगरमच्छ के आसू बहाते हैं और कहते हैं कि ये तो सरमायेदारों के साथ मिल गए। स्पीकर साहब, सरमायेदारों के साथ तो ये मिले थे दादरी में मेरे माननीय कामरेड हुक्म सिंह ने एक बात कही थी कि 2 करोड़ 14 लाख रूप्ए रामकिशन डालमियां डकार गये और अब तो वे दुनियां से भी चले गए। तो अब उनके विरूद्ध हम क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये हमको इतना पेचीदा फंसा गए कि न उसकी फैक्टरी से सिमैंट मिलता है और न ही पैसे वसूल हो रहे हैं। उस फैक्टरी का ढ़ांचा हिला पड़ा है और इन्होंने दो हजार मजदूरों के परिवार दाब पर लगा रखे हैं इनके कारनामें क्या क्या बताऊ (शोर) स्पीकर साहब,

11.00 बजे

हमने सत्ता मे आने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में बहुत से नये यूनिटस लगाए हैं। इस वर्श इस क्षेत्र में 200 नये यूनिटस आरम्भ किए हैं और वर्श अन्त तक इनकी संख्या 330 हो जायेगी।

हमने इन उद्योगों का 1 करोड़ 67 लाख यप्ये की फाइनेन्शियल असिस्टैंट दी है। इस प्रकार उद्योगों को चलाने के एिल ओर यंग इन्टरप्रन्योर्ज को नये उद्योग लगाने वालों को, जिनके पास बहुत थोड़ी पूंजी हुआ करती थी और पूंजी कम होने के कारण उद्योग नहीं लगा सकते थे, जिनको गाईड करने वाला कोई नहीं हुआ करता था, इनके लिए हमारे केन्द्र के उद्योग मंत्री जार्ज फर्नाडीज ने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सैन्टर खोलने की एक नयी योजना बनाई। इस योजना के अधीन हर जिले में 6 मैनेजर और एक जनरल मैनेजर होगा। ये इंडस्ट्रियल सैन्टर खोलने के लिए पैसे कहां से आयेंगे, कच्चा माल कहां से मिल सकता है, बने हुए माल का बेचने का प्रबन्ध कैसे हो सकता है, इन सीर बातों का प्रबन्ध करने के लिए मैनेजर और जनरल मैनेजर, नये उद्योग कर्ताओ का मार्गदर्शन करेंगे और इनको उन से सब प्रकार की सहूलियतें प्राप्त हो सकेंगी इसके अलावा स्पीकर साहब, हमने सत्ता में आने के बाद खादी बोर्ड की ओर से 17 लाख रूपये की सबसिडी बांटी है ओर सरकारी समितियों और दूसरे 3312 लोगों को भी ऋण दिए। स्पीकर साहब, गांवों में रहने वाले आर्टीजन जो घड़े बनाने का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, हाथ से दूसरे काम करते हैं, यानी जेा पुश्तैनी तौर पर अपने काम करते ळें, इनकी हालत सुधारने के लिए ऋण देकर सरकार ने उनको सहयोग दिया।

स्वामी आदित्यवेश: स्पीकर सहाब, मेरा औचित्य का प्रश्न है। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जो दस्तकार हैं, उनको सरकार पैसा दे रही है। मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ जिले का गाहला गांव है जिसमें एक नौरंगसिंह नाम का आदमी .....

श्री अध्यक्ष: आपको बोलने के लिए टाईम दिया जाएगा, उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं। यह कोई प्वायंट आफर आर्डर नहीं है, आपको बीच में इन्ट्रप्ट नहीं करना चाहिए।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमने हायर–परचेज बेसिज पर 2 करोड़ 91 लाख रूपये की मशीनरी लोगों को लगा कर दी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्श उद्यमकर्त्ताओं का चण्डीगढद्य में बुलाकर कहा था कि हरियाणा के लोगों को रोजगार देने के लिए आप हरियाणा में उद्योग लगाएं। जो भी उचित सहयोग हमारी तरफ से होगा, वह देने के लिए हम तैयार हैं। पंजाब की धरती पर जो सुविधाएं आपको मिलती हैं, वह हम देंगे। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि पड़ौस की धरती के साथ लगती हुई हरियाणा की धरती पर, पुलाहड़ा के इलाके में इलैक्ट्रिकल इक्वैपेमैंटस की बिल्डिंग बन गई है। स्पोर्टस की बिल्डिंग सांपला में, हौजरी की बिल्डिंग कुंडली में बन रही है। इसी प्रकार स्पीकर साहब, बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, अम्बाला, गुड़गांव, हिसार, राई, रोहतक और करनाल में 592 नई बिल्डिंग्ज बनी हैं। यह बिल्डिंग्ज लोगों को देंगे ताकि

लोग अपना काम–धंधा इन में शुरू कर सकें। इसी प्रकार बल्लभगढ़ में 400 शैडज बन रहे हैं ताकि जो लोग खुद मकान नहीं बना सकते, जिनके पास बहत थोड़ी पूंजी है, वे अपना काम–धंधा उन शैडज में चला सकें। स्पीकर साहब, अगर मैं सरकार की एक्टिविटीज की बात कहूं तो बहुत समय चाहिए लेकिन आपने तो मरेा समय सीमित कर दिया है, इसलिए ज्यादा न कहते हुए यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस राज में एक ही आदमी सारी मिनरल्ज का पट्टा ले लिया करता था और मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों की सेवा करता था। यह बात शाह कमीशन के सामने भी आई और उस महानुभाव के घर पर छापा भी पड़ा था जिससे 10 लाख रूपये का माल बरामद हुआ था। इस सरकार ने माइनर मिनरल्ज को लीज पर नहीं दिया बल्कि हम हर मिनरल की नीलामी करते हैं और इसके बाद अगर कोई आफर देता है तो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानते। स्पीकर साहब समूचे प्रदेश की बेकारी को दूर करने के लिए हरियाणा स्टेट सारे भारतवर्श में अनपैरलल स्टेट है। अभी 15 तारीख से 21 तारीख तक हरियाणा सरकार ने उद्योग सप्ताह मनाया था ताकि लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग आरम्भ किए जाएं। स्पीकर साहब, मैं डिबेट सुन रहा था, इस कार्याक्रम के ऊपर अपोजीशन के किसी भाई ने एक शब्द नहीं कहा। हां, किसी ने यह कहा था कि बैंक वाले इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कौअप्रेट नहीं कर रहे, कुछ आनाकारी कर रहे थे। मैं उस बैंक वालों से बात करूंगा कि हरियाणा की धरती पर चलने वाला बैंक, अगर ग्रामीण उद्योग के विकास के कलिए

हमें सहयोग नहीं देगा तो हम उस बैंक को हरियाणा की धरती पर भलिभांति चलने नहीं देगें। स्पीकर साहब, 30 साल हिन्दुस्तान की हकूमत कांग्रेस के हाथ में रही। अभी डेढ़ साल से जनता पार्टी की हकूमत आई है और डेढ़ साल से ही तालियां मल रहे हैं, खुआब ले रहे हैं कि हाय गद्दी, हाय बंगला। (व्यवधान) स्पीकर साहब, बट–वृक्ष, जो बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जब यह बोया गया था तो एक बीज के रूप में था। समय लेकर इसने एक विराट रूप धारण कर लिया जिसकी छाया में हर प्रकार के जीव–जन्तु और मनुश्य शरण लेते हैं। इसी प्रकार सरकार की नीति है कि बीज रूप में 2000 यूनिट इस पंचवर्शीय योजना में लगायेंगे।

स्पीकर साहब, मैंने उस दिन सबसिडी के बारे में कहा था। आज तक कांग्रेस सरकार बड़े–बड़े पूंजीपतियों को सबसिडी देती रही, 40 लाख रूपया हिसार क एक उद्योगपति को सबसिडी के रूप में दे दिया। हम इस तरह की सबसिडी नहीं दे रहे। हमने तय कर लिया है कि जो एक लाख रूपये से गांव में उद्योग लगाएगा उसको 15 हजार रूपया नकद, सबसिडी के रूप में दिया जाएगा।

श्री शमशेर सिंह: मजदूरों पर तो अत्याचार हो रहा है। (व्यवधान)

डा. मंगल सैन: अत्याचार की बात करते हैं। पीपली और नगीना की जनता के ऊपर जो आपने गोलियां बरसाई, लोग खून से लथपथ हो गए, मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया, क्या आप वह अत्याचार भूल गए? आप लोगों ने गोलियों से लोगौं को उड़ाया। एमरजैंसी में ट्रेड यूनियन्ज पर पाबन्दी लागा दी थी। चौ. शमशेर सिंह लैफटिस्ट हैं, सी.पी.आई. में भी रहे हैं। बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ बैठते हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है, उनकी मजबूरी हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमने सबसिडी के बारे में अपनी नीति बदली है, उसी प्रकार बैकवर्ड एरिया के बारे में भी नीति बदल रहे हैं। मैंने सदन को आश्वासन दिया था कि हम इस बात पर विचार करेंगे और जो मापदण्ड बनाया है उसके आधार पर पुनः बैकवर्ड एरियाज डिक्लेयर करैंगे। यह बात नहीं जैसे पहले होता था कि जिस पर सरकार की मेहरबानी हो गई या जिसको दिल किया, उसको बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया। मेरे भाई श्री रामकिशन बैरागी इस बारे में कह रहे थे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मामला अभी अंडर प्रोसैस है। स्पीकर साहब, मेरी कोशिश है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे निर्देश मी है कि में औद्योगिकरण के मामले मैं पूरे जोर शोर से काम करूं। यह मैं कर भी रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक छोटा साह डिपार्टमैंट भी मेरे पास है। पहले 17 आई.टी.आईज. थे, अब 19 हो गए हैं। इनके बारे में भी एक आध मिनट में बात खत्म कर

देता हूं। पहले एडमिशन अंधाधुंधर हो जाया करती थी, अब हम मैरिट पर करते हैं। पहले जे.बी.टी. और होम साईस ट्रेनिंग की दुकानें खुली हुई थीं, अब वे सब हमने बंद कर दी हैं। जो संस्था पांच साल तक किसी ऐजुकेशनल सोसायटी से रिकौगनाइज्ड होगी उसको मान्यता मिलेगी। स्पीकर साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमैंट है इसके द्वारा हम ऐसी स्किल्ड लेबर और कारीगर आदि तैयार करें जिनकी हमें आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने समय में ही अपनी पूरी बात कहते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली) माननीय स्पीकर साहब, बजट के ऊपर काफी बहस हाउस में हो चुकी है लेकिन चन्द बातें मैं भी कहना चाहता हूं। नए बजट में इस तरह जी भर के टैक्स ठोके गए हैं कि जनता सरकार के मुताल्लिक जो लोगों का ख्याल था वह अब सामने आ रहा है। किस तरह लोग बगावत कर रहे हैं इस सरकार के खिलाफ, कितने परेशान हैं वे इनके कारनामों से, यह तो हमने परसों देखा। डाक्टर साहब का शहर रोहतक हैं उसको यह अपना गढ़ भी बताया करते हैं।

डा. मंगल सैन: मेहमान नवाज भी है वह।

राव बीरेन्द्र सिंह: वहां तीन लाख लोग उमड़ पड़ थे इंदिरा जी का स्वागत करने के लिए। (विघ्न) उनकी यह इच्छा है कि किसी तरह यह राज खत्म हो और हमें इनसे निजात मिले।

यह हाल हिसार में था। (विघ्न) तो अब जनता पार्टी का वक्त खतम हो गया है। अब तो बता सिर्फ इतनी है कि कितने दिन और सिसक–सिसक कर यह जीती है।

डा. मंगल सैन: फिक्र न करो, आपका वक्त नहीं आता।

राव बीरेन्द्र सिंह: डा. साहब, मैं तो दस साल पहले उस कुर्सी पर बैइ चुका हूं।

डा. मंगल सैन: हमारी वजह से ही बैठे थे।

राव मंगल सैन: मेरे लिए इस जगह की खास अहमियत नहीं है। आपकी ख्वाहिश जरूर होगी कि मैं आऊं। (विघ्न) आपकी ख्वाहिश को मैं समझता हूं क्योंकि हम पुराने दोस्त हैं। जो मजे आप उन दिनों में लेते थे वह आज आपको नहीं मिल रहे हैं। वह दिन भी आपको याद होगा जब आप चौ. देवी लाल की वजह से परेशान रहा करते थे।

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल): मैंने ही आपको चीफ मिनिस्टर बनाया था। (शोर)

राव बीरेन्द्र सिंह: मुझे वह दिन भी याद है जब चौ. देवी लाल जी ने लोटे में नमक डाल करके कसम खाई थी कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे लेकिन एक महीने में साथ छोड़ गए। (शोर)

चौ. देवी लाल: मुझे भी वह दिन याद है जब यह अकड़ी हुई गर्दन आपने एक माली यानी सैनी से तुड़वाई थी। (विघ्न)

राव बीरेन्द्र सिंह: चौ. देवी लाल जी जो चाहे कहे लेकिन किसी कौम के ऊपर हमला करना, किसी कौम को माली करने पर मैं सख्त एतराज करता हूं।

चौ. देवी लाल: यह प्रौपेगैन्डा स्टेज नहीं है। (विघ्न)

राव बीरेन्द्र सिंह: मैं आपको बता रहा हूं कि ये लफ्ज ठीक नहीं है। आप पब्लिक जलसे में ऐसा कह सकते हैं कि मेरी गर्दन जो टेढ़ी थी, वह सीधी कर दी। वह आप कर सकते हैंख जनता आपकी भी करके दिया देगी लेकिन जो बराबर का भाई हो, उसको आप तुच्छ क्यों कहते हो? (विघ्न) स्पीकर साहब, अगर ये लफ्ज रिकार्ड से खारिज हो जाएं, तो अच्छा है।

स्पीकर साहब, इन्होंने 10 करोड़ 8 लाख रूप्ये के नए टैक्स लगाए लेकिन फिर भी 12 करोड़ 90 लाख के करीब घाटा है। ये टैक्स इन्होंने उस वर्ग पर लगाए जो पहले ही टैक्सों से दबा हुआ है। इन्होंने हलवाइयों को नहीं छोड़ा, ढाबे वालों को नहीं छोड़ा ओर बस फेयर भी साढ़े बारह परसैंट बढ़ा दिया।

चौ. देवी लाल: क्या कभी बस पर चढ़े हो?

राव बीरेन्द्र सिंह: मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिनकी तरफ से मैं चुनकर आया हूं। परन्तु क्या आप बस पर चढ़ते हो? आपको तो हवाई जहाज मिले हुए हैं।

तो स्पीकर साहब, मैं सख्त विरोध करता हूं इन टैक्सों का और उस तरीके का जिस तरीके से ये टैक्स लगाए गए हैं। स्पीकर साहब, स्टैम्प डयूटी इन्होंने 25 परसैंट बढ़ा दी। एक तरफ तो यह बात करते हैं लोन देने की, इंडस्ट्रियल यूनिटस लगाने की, बेरोजगार, पढ़े–लिखे नौजवानों को लाईसैन्स देने की ओर गरीबों को बैंकों से कर्जा दिलाने की लेकिन इनको पता होना चाहिए कि कर्जा कैसे मिलता है। पहले कोई जमीन मौर्गेज की जाती है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है जिसके ऊपर स्टैम्प डयूटी लगतीहै। इसलिए यह सारा बोझ उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी मदद करने का आप दावा करते हैं।

डा. मंगल सैन: गांवों में रजिस्ट्रेशन फी माफ है।

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सहाब चौधरी साहब ने सवा छः एकड़ तक की माल गुजारी माफ करके बड़ा तीर मारा है। इन्होंने एक हाथ से जो दिया है उससे ज्यादा दूसरे हाथ से छीन लिया है। सवा छः एकड़ की जमीन जिसके पास है उसमें और सात और आठ एकड़ वालों में बहुत मामूली फर्क होता है। एक कुनबे में ही एक किसान के पास तो सवा छः एकड़ जमीन है,

दूसरे के पास पांच एकड़ है और किसी के पास सात या आठ एकड़ है। सवा छः एकड़ से ऊपर वाले किसानों के ऊपर इन्होंने साढे 31 फीसदी मालिया बढ़ा दिया है। अब आप अन्दाजा लगाएं कि गरीब किसान का क्या बनेगा। अगर किसान की इस बारे में ये राय लें तो इनको पता चल जाएगा।

चौ. देवी लालः आपको मायूसी होगी।

राव बीरेन्द्र सिंहः मैं तो खुश हूं। जितना ज्यादा पैसा आप लगाएं उतना ही जल्दी काम ठीक होगा। मुझे कोई आपति नहीं है लेकिन यहां आकर हमारा फर्ज हो जाता है कि हम आपको समझाएं क्योंकि हम पावर में इंट्रेस्टिड नहीं हैं, लोगों की सेवा में इंट्रेस्टिड हैं।

चौ. राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, अंगूर खट्टे। (विघ्न)

राव बीरेन्द्र सिंहः अंगूर हमारे सामने ही थे और चूस–चूस कर जो अंगूर हमने छोड़े थे उन्हे ये खा रहे हैं। (विघ्न)

तो स्पीकर साहब, इसी तरीके से इन्होंने इरीगेशन के ऊपर 10 फीसदी वाटर रेट बढ़ा दिया। आप इनसे पूछें कि इन्होंने गरीबों को क्या सहूलियत दी? चाही टैक्स उस इलाके पर लगता है जहां लोग अपने खर्चे पर कुएं बनाते हैं। उन गरीब इलाकों का इस बजट में कोई ध्यान नहीं रखा गया सवा छः एकड़ तक का जो मालिया इन्होंने माफ किया वह इरीगेशन के ऊपर इस फीसदी

वाटर रेट बढ़ाकर किसानों से वसूल कर लिया जाएगा। इसी तरीके से जो टैक्स और बढ़ाए गए हैं उनका बोझ भी किसानों के ऊपर पड़ेगा। मसलन सीमेंट के ऊपर इन्होंने टैक्स बढ़ाया है। सीमेंट पहले ही नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर टैक्स लगाकर ब्लैक मार्किटिंग बढ़ाना चाहते हैं। आज किसान एक–एक सीमेंट के कट्टे के लिए परेशान है। जनता सरकार आने के बाद उसकी पैदावार पर टैक्स बढ़ रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि रूलिंग पार्टी के साथी जो जाहिरा तौर पर तो सरकार के साथ हैं लेकिन दिल से विरोध कर रहे हैं कि यह बड़ा गलत काम हो रहा है। मुझे तो एक बात का बड़ा ताज्जुब है कि सरकार तो चौ. देवी लाल की है लेकिन बदनाम * * * * मूलचन्द जैन हो रहा है। –

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब * * * * शब्द एक्सपंज होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बेचारा शब्द एक्सपंज कर दिया जाये।

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं तो उनसे पूछ कर कह रहा हूं। अगर ये उसकी बुरा मानते हैं तो मुझे मान लें। मैं बेचारा हूं।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, वे मेरे जैसों का कून्डा करके मिनिस्टर बन गये, क्या वे बेचारे हैं? (हंसी)

राव बीरेन्द्र सिंह: यही बात तो मैं कह रहा हूं आपका तो उन्होंने कून्डा कर दिया। अब तो आपको आवाज सुनाई दे गई।

स्पीकर साहब, मैं कुछ सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मैं इनको यह भी बताना चाहता हूं कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। जिन कर्मचारियों की वजह से आप हकूमत चला रहे हैं उन पर और जनता पर आप रोड रोलर फेर रहे हैं। ट्रेजरी बेचिंज के साथियों ने भी आवाज उठाई है और हमारी भी यही आवाज है कि यह टैक्स वापिस होने चाहिएं और मुझे आशा है कि सरकार इन टैक्सों को वापिस लेगी।

स्पीकर साहब, इस बजट में भी टैक्स प्रोपोजल है। बजट में कोई भी प्रोपोजल हो वह सीक्रेट होती है और वह एकदम से हाउस के सामने आनी चाहिए। हमारे फाइनैन्स मिनिस्टर साहब ने एक नया टैक्स लगाने की तरफ इशारा यिका है कि बार्डर के बाहर जो भी माल जायेगा चाहे वह अनाज है या इन्डस्ट्री गुडज हैं उस पर टैक्स लगेगा ताकि हरियाणा में जो भी पैदावार हो सरकार को उससे काफी फायदा हो। इस सरकार ने सबसे पहले तो किसान को मारने का काम पूरा कर दिया। अगर कोई भाई पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव या बहादुरगढ़ से किसी और मंडी में माल ले जाये तो उस पर टैक्स लगेगा ताकि किसान अपने माल का फायदा न उठा सके। इस सरकार ने तो और भी ज्यदा रिश्वत को बढ़ा दिया। सबसे ज्यादा गलत बात तो यह हुई

हे कि टैक्स का इशारा दे कर बजट की लिकेज की है बजट में इन्होंने पूरी तरह से डिटेल नहीं बताई कि वे किस चीज पर टैक्स लगाने जा रहे है। और यह भी नहीं बताया कि कितने टैक्स लगायेंगे। आप इन्डस्ट्रियलिस्टस को बुलाना चाहते हैं कि आओ हम तुम्हारे पर टैक्स लगा रहे हैं। किस तरीके से उनको मनवायेंगे। डाक्टर मंगल सैन जी भी इंतजार कर रहे हैं कि फरीदाबाद और सोनीपत के लोग उनके पास आयें कि हमें इस टैक्स से बचाओ, हम आपके सेवक हैं। (विघ्न) चीफ मिनिस्टर साहब आपने तो मुझे सलाह देने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने आपकी मानी नहीं और इसी बात से आप नाराज रहते थे (विघ्न) डाक्टर साहब अपने तो मुझे कोई बात गलत नहीं बताई थी, आप तो मेरे से खामख्वाह ही नाराज होते हैं। आप तो हमेशा यही कहा करते थे कि चौधरी देवी लाल की बात मानी तो कमीशन की इन्कवायरी भुगतने फिरोगे।

स्पीकर साहब, सरकार ने डिवैल्पमैंट की काफी बातें की है। कुछ अच्छी बातें भी की हैं और मेरे दोस्त कहा करते हैं कि अच्छी बातों की तो अपोजीशन को तारीफ करनी चाहिए। स्पीकर सहाब, सरकार ने सरकारी कर्म्चारियों को एडीशनल डी.ए. दिया। क्या यह उनका हक नहीं था? यह तो पहले ही मिल जाना चाहिए था। अब आपने देना मंजूर किया है। इसके लिये भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि आपने एम्पलाइज की तरफ ध्यान तो दिया। आपने वैट्रनरी डिपार्टमैंट के डाक्टर्ज की और पी.डब्ल्यू.डी. के

वर्कर्ज की सैलरी बढ़ाने की बात की है। उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। कोई बात तो ठीक करने की कोशिश की है। यह उनका जायज हक था * * * * * *

श्री बलदेव तायल: आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्शित करना चाहता हूं कि असैम्बली का मैटर हाउस में नहीं उठाना जा सकता। यह पहले से ही कनवैंशन है:

Mr. Speaker: Kindly do not refer to the Assembly Secretariat.

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, श्री तायल ने जो एतराज किया है मैंने कोई ऐसी क्रिटिकल बात नहीं की। मैंने तो उनके साथ जो डिस्क्रिमेशन हो रही है उसके बारे में बात की है।

Mr. Speaker: My ruling is that nothing pertaining to the Assembly Secretariat and its staff be brought on record and what has been said should be expunged.

Rao Birende Singh: I would like to bring to your kind notice that the rule forbids mentioning of things which are critical of the working of the Assembly staff. That is the meaning of the rule.....

श्री अध्यक्ष: असैम्बली के स्टाफ के बारे में कोई बात नहीं उठायी जानी चाहिए। मैंने अपनी रूलिंग दे दी है। जो कुछ कहा गया है उसे एक्सपंज कर दिया जाये।

चौ. लाल सिंह: * * * *

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब, मेरी माननीय राव साहब से प्रार्थना है कि वे अपने पुराने साथियों का नाम याद रखते हैं लेकिन मेरे जैसी नाचीज हस्ती का भी तो नाम याद रख लिया करें।

राव बीरेन्द्र सिंह: अगर सरकार यह चाहती है कि लोगों को मौजूदा टैकस का बोझा बर्दाश्त करना चाहिए तो सरकार को सबसे पहले यह भी सोचना चाहिए कि लोगों की पेटी सख्त करने से पहले अपनी पेटी को भी तो सख्त करे। सरकार जो एक्सपैंडीचर कर रही है उसको भी तो कम करना चाहिए। हर बजट के बारे में यह भी सोचना होता है कि फालतू खर्चे को कैसे कम करें। अपने खर्चो को भी तो घटाओं, वैस्टेज को कम करो तभी तो दूसरों पर लागू कर सकते हो। आप लोग कफद अपने टेलीफोज के बिल कम करो। कुछ टूरों का कम करों। जितने भी कारपोरेशंज के चेयरमैन बनाये हुए हैं, इनको हटाओ। स्पीकर साहब, कोई पचास एम.एल.एज. को कारपोरेशंज का चेयरमैन बनाया हुआ है। अगर आप दो और बढ़ा दे तो पूरे 52 पत्ते ताश के हो जाएंगे फिर चाहे जिस तरह से मर्जी आप खेलें लेकिन यह जो आप घरौंडे बना रहे हैं, ये ढह भी जाया करते हैं। ये 52 पत्ते हवा में उड़ जायेंगे।

चौ. देवी लाल: आपने भी कोशिश की थी।

राव बीरेन्द्र सिंह: मैंने कोशिश नहीं की थी। आपको तो यह जानता ही नहीं छोड़ेगी। आप यह न समझें कि आप अपने प्रोग्राम की वजह से काम चला रहे हैं। यह तो इंदिरा गांधी का आक्सीजन हे जिसका नाम लेकर आप जी रहे हैं (व्यवधान)। स्पीकर साहब, बहुत ज्यादा वैस्टेज हो रही है। आ कारपोरेशन्ज में एम.एल.एज. हैं, बैकों में एम.एल.एज. हैं और अगर कोई एम.एल.ए. नहीं मिलता तो वहां एम.एल.ए. का रिश्तेदार लगा दिया जाता है और उसके ऊपर कोई चौधरी साहब का डिस्पिलिन नहीं है, कोई इनका डर नहीं हैं। वे मनमानी कर रह हैं। सर्विसिज के अन्दर बहुत ज्यादा भ्रश्टाचार हैं। जिन लोगों के इन्टरव्यू हुए तीन–तीन, चार–चार महीने हो गए हैं उनका कोई सिलैक्शन नहीं हुआ है। आप किस बात की इन्तजार कर रहे है? क्या इस बात की इन्तजार कर रहे है कि कोई फैसला किया जाए कि किसको नौकरी देनी हैं और किसको नहीं देनी है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डा. कमला वर्मा): आपके जमाने में सर्विसिज में जो कुछ हुआ था, हमें आकर उसको ठीक करना पड़ा।

राव बीरेन्द्र सिंह: आप उस वक्म की बात न करें। आप जो कुछ कर रहे है। उसकी बात करें। जो आपका प्रोग्राम है उसके मुताबिक कहें। आप पीछे के बारे में कब तक गाली देकर जिन्दा रहेंगे। स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि एक्सपैन्डीचर कम करें। स्पीकर साहब, सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने एक मिसाल कामय

की है। चौ. चरण सिंह ने एलान यिका है कि हम एक एक्सपैंडीचर कमिशन बनाएंगे ताकि सरकार का खर्चा घटाया जा सके, उस पर विचार किया जा सके कि कहां पर कमी की जा सकती है। आप क्यों नहीं ऐसा कमिशन बनाने के बारे में सोचते हैं (व्यवधान) आप ऐसी बात कहां सोचनते हैं। आप तो यह सोचते है कि पचास के करीब तो एम.एल.एज. चेयरमैन बना दिए हैं ओर अस्सी एम.एल. एज. को किस तरीके से फिट किया जा सकता है। आप एकपैंडीचार का घटाने की बात कहां करते हैं डाक्टर साहब का एक लाख 22 हजार रूप्ए का टैलिफोन पर खर्च आता है। ये खर्च कम करने की बात कैस सोच सकते हैं .....

डा. मंगल सैन: हम काम करते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह: आप काम कहां करते हैं। आप तो शाखाओं में जाते हैं आप तो शाखाएं अटैन्ड करते होगें।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहबख मुझे इनकी समझ पर तरस आता है। इनको पता होना चाहिए कि शाखाओं में टैलिफोन नहीं होते।

राव बीरेन्द्र सिंह: डा. साहब, आप ही 1967 में बताया करते थे कि मुझे फुरसत नहीं है। मैं तो शाखा में जा रहा हूं (व्यवधान)। जब भी आपको टैलिफोन किया जाता था तो पता लगता था कि डा. साहब शाखा में गए हैं। (व्यवधान) स्पीकर साहबख जनता में अपना मियार कायम करने के लिए अपनी पेटी

कसनी पड़ती ळै। अगर ये जनता के सेवक हैं तो मैं इनसे हाथ जोडकर नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आइन्दा इलैक्शन में जीतकर आना है तो जितने चेयरमैन बने हुए हैं, वे सारे अस्तीफा दे दें ओर फिर देखिए जनता में क्या वाह–वाह होती है। आप मैम्बरों के लिए क्या–क्या कर रहे हैं। सारा कुछ अपने ही लिए किए जा रहे हो और अपने लिए करके जनता के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। इससे ज्यादा जनता के साथ ओर क्या खिलवाड़ हो सकता है। आप डिवल्पमैंट की बात करते हैं। करप्शन तो आप से रूका नहीं। आप प्रोहबिशन की बात करते हैं और कहते हैं कि सैन्टर से पचास परसैन्ट पैसा लेंगे लेकिन हालत यह है कि गुड़गांव में अभी पिछले दिनों शराब के ठेके का आक्शन किया गया। आपके अफसरों ने आक्शन किया। रूल यह है कि जो आक्शन हो, उसका दस परसैन्ट तो स्पोट पर ही दिया जाएगा ओर पच्चीस परसैंट या कुछ और सात दिन के अन्दर दिया जाएगा। वहां पर जिस आदमी को शराब का ठेका देना था उनसे मिलीभगत कर ली और दूसरे आदमी जिसने ज्यादा बोली दी थी उसको तबदील कर दिया। उसको कहा गया कि तुमको पचास परसैंट देना पड़ेगा लेकिन कायदा यह है कि जिसने बोली दी उसको सात दिन के अन्दर पैसा देना पड़ेगा .....

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौ. शेर सिंह): स्पीकर साहब, ऐसाी है कि जितनी बोली लगती है उसका दस परसैन्ट सात दिन के अन्दर बोली देने वाले को जमा करना पड़ता है।

लेकिन रूल्ज में यह भी प्रोविजन है कि अगर औक्शनर यह महसूस करता हे कि बोली देने वाले की फाइनेशीयल पोजीशन ठीक नहीं है तो रैवैन्यू को सिक्योर करने के लिए वह बिडर से विड का एक तिहाई पैसा एट दि स्पाट जमा कराने के लिए कह सकता है। स्पीकर साहब, पचास परसैन्ट का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह: शेर सिंह जी, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको आप तसदीक करवाएं। मैं तो यही कह रहा हूं कि रूल्ज तोड़े गए। एक शख्स ने 18 लाख की बोली दी। उससे कहा गया कि फौरन आधा पैसा जमा करो। उसने कहा कि मैं सात दिन के अन्दर भर दूंगा। औकशनिंग आफिसर ने काह कि अगर पैसा नहीं भरोगे तो अठारह लाख की बोली कैन्सिल हो जाएगी। दोबारा बोली लगाई गई और वह 16 लाख की गई। इस सरकार ने एक बोली के अन्दर दो लाख रूपया खो दिया। यह गुड़गांव की बात है। स्पीकर सहाब, इस तरह से हरियाणा में काम हो रहा है।

चौ. शेर सिंह: आप दे दो अठारह लाख रूपया, हम आपको बोली छोड़गे।

राव बीरेन्द्र सिंह: अगर आप सुनना नहीं चाहते तो दूसरी बात हैं अगर सुनना चाहता हो तो शान्ति से सुनें (व्यवधान)। प्राइसिज खूब नीचे आई हैं। गन्ने पर आप सबसिडी दे रहे हैं। कोआप्रेटिव शूगर मिलों को तीन करोड़ रूपया किसानों

को देने के लिए दिया जाता रहा है लेकिन दूसरी ओर मुकदमें चल रहे हैं। स्पीकर साहब, यह इन्होंने माना है कि 1 करोड़ 10 लाख का कोआप्रेटिव्ज में घपला है। जिस कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट के अन्दर दो करोड़ रूप्ए का ऐम्बैजमेंट हो तो आप क्या बात करते हैं कि हम कोआप्रेटिव को बढ़ावा दे रहे हैं।

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, यह इनकी पार्टी के जमाने की बात है, यह तो इनके वक्त की बात है।

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट दरअसल कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट रहा ही नहीं। यह तो इजारदारी बन गई है। कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट की स्पिरिट ही खतम है। आप सारे इंस्टीटयूशंज का तोड़कर उनमें अपने साथियों को नौमिनेट कर रहे हैं। एक्ट में प्रोविजन है कि अगर सिकी बोर्ड को या इंस्टीच्यूशन को सुपरसीड किया जाए तो कम से कम एक तिहाई पहले मेम्बरों को लिया जाएगा लेकिन आप अपनी मर्जी से बोर्ड बनाकर पालिटिकल आदमियों को नौमिनेट कर रहे हैं। आपने सोसायटी का कोई भी मैम्बर नौमिनेट नहीं किया। आप तो पोलिटीकल कौआप्रेशन की बात कर रहे हैं। काआप्रेटिव मूवमैंट तो इस सरकार ने खत्म कर दिया है। जब आप पोलिटीकल आदमियों को नौमिनेट कर रहे हैं तो फिर कोआप्रेटिव सोसायटी कहां रही, इंस्टीटयूशंज कहां रहे? आप चलाए जाएं, जिस तरीके से चलाना चाहते हैं। मैं तो खुश हूं कि अगर आप कोई भी बात

ठीक करने की कोशिश न करें (हंसी) और चाहते तो हम भी दिल से यही हैं कि आप ऐसा ही करते रहें।

Mr. Speaker: Rao Sahib, please wind up your speech. You have taken 30 minutes.

राव बीरेन्द्र सिंह: बस जी, मैं छोटी सी बात और कह कर जल्दी ही वाइंड अपन करता हूं। यहां पर इनकी तरफ से फल्ड की बात भी कही गई और शिकायत की गई परमात्मा की केवल परमात्मा तो कर्म देखकर ही कर्म करता है। यहां पर कहा गया कि 1977 में बढ़ते हुए फ्लड के कारण हरियाणा डूब गया, उससे मुशकिल से तैर कर निकले ही थे कि 1978 मैं फिर बाढ़ आ गई, तो फिर ये बताएं कि यह सबि कस की वजह से हुआ (विघ्न)

आवाजें: आपकी वजह से।

राव बीरेन्द्र सिंह: क्या हमने भगवान से कहा था। स्पीकर साहब, 1978 हरियाणा डूब गया और अब उसके बाद 1979 में जब आप बजट पेश कर रहे थे जो आपकी हरियाणा विधान सभा के ऊपर ओले पड़े चण्डीगढ़ में पड़े और कहीं नहीं पड़े (हंसी) स्पीकर साहब, ओलों के कारण रोहतक जिले में, सोनीपत में, हिसार में और महेन्द्रगढ़ में काफी तबाही ही गई, यह सब किस का नतीजा है? यह सब इस सरकार की बदौलत से हुआ। स्पीकर साहब, 1977, 1978 ओर 1979 तीन साल देख लिये आपने। ये इसी कारण से करोड़ों रूपया रिलीफ के लिये लोगों

को दे रहे हैं। मेरा तो सरकार से कहना है कि आप इस काम के लिये डबल पैसा रखिये क्योंकि आपके ऊपर भगवान की दया पूरे जोरों से ही रही है.....

आवाजें: स्पीकर साहब, क्या राव साहब बजट पर बोल रहे हैं?

राव बीरेन्द्र सिंह: हां जी, मैं बजट की बात कर रहा हूं। बजट में यह सब कुछ प्रोवाइडिड है और जब तक आप यह काम पूरा नहीं करोंगे तब तक भगवान भी आपके ऊपर खुश नहीं होगा.....

डा. मंगल सैन: हां जी, मैं बजट की बात कर रहा हूं। बजट में यह सब कुछ प्रोवाइडिड है और जब तक आप यह काम पूरा नहीं करोंगे तब तक भगवान भी आपके ऊपर खुश नहीं होगा. .....

डा. मंगल सैन: राव साहब, यह ज्योतिश कब से शुरू कर दिया?

राव बीरेन्द्र सिंह: डाक्टर साहब, मैंने पहले ये सारी बातें कहीं थीं और मेरी बातें सच्ची ही निकलीं। स्पीकर साहब, अब मैं आगे बताता हूं कि इन्होंने सतलुज यमुना लिंक कैनाल के लिये 16 करोड़ रूपये रखने की तजवीज की है। मैं इनसे पूछता हूं कि क्या पंजाब वालों ने आप का हक मान लिया है? आप आज तक सारे हरियाणा की जनता को भुलावा देते रहे हैं और इस

हाउस को भी भुलावा देते रहे हैं। चौ. देवी लाल जी चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें पर पंजाब वाले कुछ भी नहीं देने वाले। अभी–अभी चौ. देवी लाल जी पंजाब में जाकर उदघाटन करके आये हैं, बस पानी बहता हुआ ही पीछे जा रहा है। स्पीकर साहब, मैं इनसे पूछता हूं कि कभी इन्होंने ऐसे कामों में पब्लिक ओपीनियन क्रिएट करने की कोशिश की है, नहीं की। किसी को साथ लेने की कोशिश की है, किसी की समझ का फायदा उठाने की कोशिश की है? अब क्या हो रहा कि पंजाब वालों ने दफा 80 के तहत लीगल नोटिस दे दिया है और वे सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर जा रहे हैं कि हम रावी ब्यास के पानी के लिए हरियाणा का हक नहीं मानते। इधर इतना होते हुए भी ये कह रहे हैं कि हम इसके लिये सब कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं इन से पूछता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि पंजाब वालों ने सैक्शन 80 के तहत इन्हें नोटिस दे रखा है?

आवाजें: यह तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा।

राव बीरेन्द्र सिंह: मैंने तो अखबार में पढ़ा है। आप लोग तो यहां पर इस बारे में बताते नहीं है और चौ. देवी लाल जी को कुछ पता ही नहीं लगता क्योंकि न वे अखबार पढ़ते है और न ही आप लोग इन्हें कुछ बताते हैं।

चौ. देवी लाल: मेरा पता तो आपको लगता है।

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, सरकार ने जवाहर लाल नेहरू कैनाल बनाई है जिससे बहुत सारे सूखे इलाकों के अन्दर पानी पहुचाया जाएगा लेकिन उसके ऊपर कोई पुल वगैरह नहीं बनवाया गया है और दूसरी बात यह भी है कि अभी तक उसके अन्दर पानी भी नहीं आ गया है। पानी अगर नहीं आयेगा तो यह 50 करोड़ रूपया आपका किस काम का रहेगा? क्या आपको पानी देने की उम्मीद है, मेरे विचार से तो आप पानी नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से यहां पर टयूबवैल्ज की बात भी चलती रही। पिछली बार सरकार ने 125 सरकारी टयूबवैल्ज लगाए मगर एक भी टयूबवैल महेन्द्रगढ़ जिला के अन्दर नहीं लगाया गया। इसी तरह से सरकार 1979–80 में 180 टयूबवैल्ज लगाया चाहती है। ये टयूबवैल्ज जहां पर नहरें हैं वहां पर पानी आगुमैंट करने के यिल लगाए जा रहे है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उन सूखे इलाकों के साथ बड़ा अन्याय होगा जहां पर कि पानी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से कहूंगा कि अगर आप ऐसा एलान करेंगे कि सूखे इलाकों में ज्यादा से ज्यादा टयूबवैल्ज लगाये जाएंगे तभी लोगों को तसल्ली होगी।

स्पीकर सहाब, अब मैं रोड्ज की बाबत और वाटर सप्लाई की स्कीम के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। सरदार लछमन सिंह बैठे हैं, उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा (हंसी) क्योंकि यह हमारे पुराने साथी हैं और साथ इनका कालका का इलाका भी काफी पिछड़ा हुआ है। 174 वाटर सप्लाई स्कीमज में से सरदार

साहब, 21 अपने हल्का में लगवा लें तो मुझे कोई एतराज नहीं क्योंकि वह इलाका काफी पिछड़ा हुआ है और पहले भी वहां यह काम नहीं हो सका। अब वहां यह काम सरकार द्वारा करवा लिये जाएं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा लेकिन 174 में किस प्रकार ऊंच नीच करके डिवैल्पमैंट कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आता। 174 में से हिसार में 35 सिरसा में 25 अम्बाला में 28 और कांस्टीचुएन्सी के हिसाब से देखें .....

आवाजें: राव साहब अमाउट भी बता दो।

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सहाब, मैं अमाऊंट भी बतला देता हूं। भट्टू कलां जोकि चौ. देवी लाल जी का हल्का है, वहां पर 29 लाख का काम हुआ है, नारनौल में 14 लाख का, बाकी जगहों पर एक–एक लाख का और उसके बाद 50 हजार। इस तरह आहिस्ता–2 यह रकम कम होती गई। जहां तक सड़कों का बनाने का सवाल है, सिरसा के अन्दर 169 किलोमीटर लम्बी सड़के बनाई गई हैं जबकि वहां पर मैंने इनके कहने से भी रोडज बनवाई थीं। जब सैकिण्ड प्लान बन रही थी तो उस वक्त मैं पी. डब्ल्यू.डी. का इंचार्ज था।

Mr. Speaker: Rao Sahib, you have taken 40 minutes. Now please wind up.

राव बीरेन्द्र सिंह: हिसार के अन्दर 156 किलोमीटर और उसके मुकाबिले में महेन्द्रगढ़ में सिर्फ 40 किलोमीटर सड़कें

बनीं। तो इस प्रकार से अगर सरकार करेगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी।

चौ. देवी लाल: कृपा करके वाटर सप्लाई स्कीम्ज महेन्द्रगढ़ की भी बतला दो। साथ में पैसा भी बता दो।

राव बीरेन्द्र सिंह: मैं बता देता हूं। महेन्द्रगढ़ में केवल 12 वाटर सप्लाई स्कीम्ज थीं। जाटूसाना, महेन्द्रगढ़, अटेली और बावल, जहां की बहिन शकुन्तला जी बैठी हैं, इन चार हल्कों को तो वाटर सप्लाई स्कीम्ज से बिलकुल ही वंचित कर दिया गया है। मतलब कि 12 में से चार बिल्कुल गायब कर दिये गये हैं और सिर्फ दो हल्कोकं में यह वाटर सप्लाई स्कीम्ज दी हैं। तो स्पीकर साहब, आप ही बताएं कि यह दोभत नही ंतो और क्या है। मेरी रिक्वैस्ट है कि सबको दो लेकिन बांट कर दो। हमारा कया हे, हम तो चुटाला जाकर के भी पानी पी लेंगे। वहां पर एक हस्पताल भी है। चौ. देवी लाल जी की मारफत दालिख भी हो जाएंगे। हमारा काम तो चल जाएगा लेकिन बाकी लौगों का और पार्टी के एम. एल.एज. का तो ख्याल रखें। इसके साथ–साथ मैं यह कहूंगा कि आप कुरप्शन को भी बन्द करो और डिस्पिलन भी रखो। जो एम. एल.एज. को औहदे दे रखे हैं, उनसे वह महकमें वापिस लेकर, औहदे वापिस लेकर लोगों का विश्वास हासिल करो और जनता के दिल में विश्वास पैदा करो। लेकिन एम.एल.एज. चौधरी साहब की मानेंगे कहां * * * *

चौ. देवी लाल: स्पीकर साहब, यहां पर इस समय बजट पर डिस्कशन के अलावा दूसरी बात कहना मुनासिब नहीं हैं।

Mr. Speaker: Please leave out the central politics. It should not be discussed.

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, * * * * वह सारी बात एक्सपंज करवाई जानी चाहिए।

Mr. Speaker: Nothing about central politics be brought on record.

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं इतना ही कह कर अपना स्थान लेना हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया।

चौ. देस राज (इंदरी): स्पीकर साहब, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन इसमें जो टैक्सिज की प्रोपोजल की गई है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान और मजदूर के लिए हर वक्त सोचते हैं और हमारे वित्त मंत्री जी भी उसी स्तर के हैं इसलिये यह जो टैक्सिज की प्रोपोजल आई है उसके बारे में मुझे उम्मीद है कि वे इस पर दोबारा सोच विचार करेंगे और कुछ राहत जरूर देंगे। वित्तमंत्री साहब ने अपनी बजट स्पीच मे कुद डिवैल्पमैंट एक्टीविटीज का जिक्र किया। उसको लेकर इरीगेशन के बारे में जिक्र चला था कि वाटर कोर्सिज पक्के लिये जा रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। कंवर राम पाल सिंह जी ने

भी कहा था कि वाटर कोर्सिज पक्के होने चाहिएं और अगर ये पक्के नहीं होंगे तो चूहे इनमें पूरा पानी नहीं चलने देंगे। इरीगेशन के लिए बजट में अच्छा प्रोविजन किया गया है। अगर खुश्क खेतों को पानी मिल जाए तो इससे हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं जमना नगर में एम.आई.टी.सी. के टयूबवैल पहले भी सन् 1971 में लगे थे और अब 1979–80 में 180 टयूबवैल्ज और लगेंगे। मेरा सरकार से निवेदन यह है कि जिस इलाके में पीन नहीं हैं वहां तो पानी जरूर दो लेकिन जिस इलाके से आप पानी लेते हो उसका भी तो पूरा ख्याल रखो। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, चौ. हर स्वरूप बूरा पदासीन हुए) यह बात मैंने मुख्यमंत्री तथा सिचाई मंत्री दोनों से कही थी कि जो टयूबवैल्ज आगमैंटेशन कैनाल पर पहले लगे हुए है उनकी वजह से किसानों को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि पानी कालैवल बड़ा डीप हो जाता है और किसानों को री–बोरिंग करवानी पड़ती है। इसलिए अगर वहां पर और टयूबवैल्ज लगेंगे तो किसान तो बेचारा मारा जाएगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आगमैंटेशन कैनाल पर और टयूबवैल न लगाए जाएं और जिन किसानों ने अपने टयूबवैल्ज लगा रखे हैं उनके बारे में आप सोचें। मैं चाहता हूं कि लिफ्ट इरीगेशन को भी बढ़ावा दिया जाए लेकिन जमना नगर के किसानों का भी ध्यान रखा जाए। इसके बाद मैं फ्लडज के बारे में कहना चाहता हूं कि फ्लडज की रोकथाम के लिये भी बजट में बहुत अच्छा प्रोवीजन किया गया है। कांग्रेस सरकार ने इस काम के

लिए केवल दो करोड़ रूपया रखा था लेकिन हमारी सरकार ने इसके लिए 18.82 करोड़ रूपया रखा और 1979–80 में इसको बढ़ाकर 20 करोड़ रूपया कर दिया है। 1978 में जो फ्लड आया उससे बड़ी बर्बादी हुई। रोहतक, जींद और सोनीपत में तो फ्लड की वजह से बहुत ही बर्बादी हुई लेकिन हमारी सरकार ने वहां पर बहुत सराहनीय काम किया। सरकार ने गांव गांव में रिंग बांध बांधे और ड्रेन खुदवाई। इसी प्रकार से पिछले साल मारकंडा और टांगरी ने लोगों की बड़ी बर्बादी की। उस समय भी सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया। सरकार ने लोगों को कर्जे दिए, चारा दिया, अनाज दिया और जिनके मकानों को नुक्सान पहुंचा उनको तीन–तीन सौ रूप्ये ग्रांट भी दी। फ्लडिड एरियाज में मुख्यमंत्री जी, मंन्त्रिगण तथ गवर्नर महोदय खुद गए और लोगों की हालत का जायजा लेकर उनको सहायता पहुंचाई। मैं भी अपनी कांस्टीच्यूएंसी के हर गांव में गया। लोगों को जो राहत मिली उसके लिए वे सरकार को बहुत सराह रहे थे। वे कहते थे कि इतनी राहत हमें आज तक कभी नहीं मिली। इसके बाद मैं फारैस्ट के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। डेजर्ट को रोकने के लिये हमारी सरकार की और सैंटर की जो स्कीम या प्रोग्राम है यह बहुत कामयाब रही है। दरखत जहां डेजर्ट को रोकने में सहायता करते हैं वहां ये फ्लड को रोकने में भी सहायता करते हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जमना के साथ साथ फ्लड प्रोटैक्शन के लिए दरखत लगाए जाएं। एक बात मैं और कहूंगा कि कलानौर से लेकर चुगांवा तक 16 किलोमीटर का गैप है और वहां पर कोई

बांध नहीं है। यह बात मैंने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में भी कही थी। वहां पर यह कहा गया कि यह मामला जमना कमेटी के पास है। अगर सरकार उस इलाके का बचाव करना चाहती है तो वहां पर बांध बांधा जाए जिससे जमना नदी से फ्लड की बर्बादी कम होगी। इसके बाद मैं बिजली के बारे में भी दो बातें कहना चाहता हूं। जब से हमारी जनता सरकार आई है तब से हरियाणा में 22 घंटे बिजली मिल रही है। काग्रेस राज में जो हालत थी वह सबको मालूम है। किसानों को अगर कभी बिजली मिलती भी थी तो रात के समय मिलती थी और वह भी जब किसान रात को जाडे के समय में अपने टयूबवैल पर पहुंचता था तो वहां पहुचते ही बिजली गायब हो जाती थी। लेकिन आज किसान को रात को भी और दिन को भी बिजली दी जाती है यानी बिजली की सप्लाई रैगुलर है। इसके बाद जो बात मैं कहना चाहता हूं उसकी अनाउंसमैंट असैम्बली में भी हो चुकी है कि जिस किसान ने अपने टयूबवैल पर चारा काटने की मशीन लगाई हुई है उस पर 15 प्रतिशत डियूटी लगती है। मेरी प्रार्थना है कि उसको एक अप्रैल से जरूर खत्म कर दिया जाये। इसके बारे में यहां पर अनाउसमैंट भी हो चुकी है कि एक अप्रैल से खत्म कर देंगे। इसके साथ साथ एग्रीकल्चार के लिये भी बजट में काफी प्रोवीजन रखा गया है। अनाज की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी सरकार ने बहुत सराहनीय काम किये हैं जैसे सरकार ने किसानों को बीज पर सबसिडी दी, खाद पर दी और गन्ने पर भी दी। लेकिन गन्ने के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बाकी सब मिलों में यह सबसिडी दे दी गई

लेकिन जमना नगर के शूगर मिल में अभी तक यह सबसिडी नहीं दी गई है। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि यह सबसिडी किसानों को जल्द दिलाई जाये ताकि उन्हें राहत मिल सके। अभी कुछ पता चला था कि इस सबसिडी की रकम को कनवर्ट कर रहे हैं। अगर सैंटर का ऐसा फैसला है तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन जहां पर फ्लड आए हैं और ओले पड़े हैं वहां पर यह सबसिडी जरूर दी जाए।

12.00 बजे

चेयरमैन साहब, मैं फार्मर्ज के बारे में कहना चाहता हूं। वे बेचारे दिन रात चाहे गर्मियों हो या सर्दियों हों या बरसात हो, घर से बारह रह कर काम करते हैं, उसके पास सोने के लिए टाईम नहीं है, उसे ऊपर कुदरत का कंट्रोल रहता है। उसकी हालत देखते हुए, नेचर की क्लैमिटीज को देखते हुए मैं यह चाहूंगा कि जैसे पंजाब में क्राप्स की इन योरैंस कर रहे हैं वैसे ही हरियाणा में भी कोई स्कीम चालू की जानी चाहिए। आप जाने हैं कि किसान की फसल कभी बाढ़ से, कभी औलों से और कभी तेज हवाओं से बरबाद होती है। खु की भी काफी होती है परन्तु खु की के बारे में तो मैं यह कह सकताह हूं कि वह तो अब दूर हो जायेगी क्योंकि बिजली पानी दोनों प्र्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं। चेयरमैन साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर कहा गया कि किसानों को फर्टिलाईजर के लिए भी सबसिडी दी गई है परन्तु मेरे देखने में नहीं आया है और जहां तक राव

साहब ने कार्पोरे ान के बारे में फरमाया तो उनमें से एक वेयर हाउसिंग कार्पोरे ान का मैं भी चेयरमैन हूं और अब वे भी चेयरमैन बनना चाहते हैं। मैं उनको इस बारे में इन्फर्मे ान देना चाहता हूं कि मेरे पास न कार है, न कोठी है न ही मैं टेलिफोन की फैसीलिटी अवेल करता हूं और न तनख्वाह लेता हूं। हमारी पूरी कोि ा ा है कि जनता का जैसे भी भला हो सके, करें। हम जनता का पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं। जब कुदरत का जिक्र आया था तो राव साहब ने यह भी कहा कि जनता सरकार के आने के साथ साथ कुदरत ने भी प्रकोप दिखाया है, यह उनका इम्तहान है वे भुगत रहे हैं। आपको मालूम है कि आदमी को इस जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में कभी नहीं मिलता है जैसे कि हमारे भाास्त्र कहते हैं, यह तो पिछले कर्मों का फल मिल रहा है। पहली सरकार ने एमरजेंसी के दौरान अत्याचार किये जिनके कारण आज प्रकृति का प्रकोप हम भुगत रहे हैं। फर्टिलाईजर के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी एक दिन सप्लीमैंटरी में जिक्र किया था। फर्टिलाईजर इम्पोर्ट होती है जो कि वनज मं बहुत कम होती है। मैंने खुद जा कर बराड़ा की मंडी में देखा है, सन् 1975 की खाद रखी हुई है। मजदूर खाद के कट्टे खोलने में लगे हुए थे। आप अंदाजा लगाईये कि अगर किसान वह खाद अपने खेतों में डालेगा तो फसल का हाल क्या होगा। वह खाद नै ानल फर्टिलाईजर लिमिटिड से आई हई थी। मैं यह चाहूंगा कि यह खाद किसानों को सप्लाई न की जाये, जो सप्लाई कर दी गई है वह वापिस ले ली जाये और जो बाकी है उसे नश्ट कर दिया जाये। इस खाद से

एक भी दाना नहीं होगा जब किसान यह खाद अपने खेतों में डालेगा तो फसल न मिलने पर वह कितना निरा ा होगा, यह आप अंदाजा नहीं लगा सकते। चेयरमैन साहब, इसी प्राकर एग्रीकल्चरल प्रोडक ान को भी बढ़ावा देना चाहिए जोकि यह सरकार दे रही है। इसी तरह साईटिफिक स्टोरेज की भी जरूरत है। अगर साईंटिफिक स्टोरेज नहीं होंगे तो फसल खराब हो जायेगी। अभी पिछले दिनों बरसात में चावल बाहर था, गेहूं भी पूरी तरह स्टोर में नहीं रखा गया था। कोई भी अनाज खराब नहीं होगा यदि अनाज को रखने के लिए स्टोर्ज हों। अगर एफ.सी.आई. या सैंटर और राज्य की दूसरी एजैंसीज मार्किट से किसान का अनाज खरीदें और ज्यादा से ज्यादा स्टोर करें तो इस नुक्सान से बचा जा सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा में आज 15 लाख 32 हजार टन अनाज रखने की कैपैसिटी है। एफ.सी.आई. की इस वर्श चार लाख टन और अनाज रखने की कैपैसिटी बढ़ जायेगी। आप जानते हैं कि हमारे हरियाणा में पहले 15 लाख 32 हजार टन की कैपैसिटी है और 1979–80 में 21 लाख 72 हजार टन अनाज, फसल के आंकड़ों के हिसाब से स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह 6.50 लाख टन और अनाज रखने की कैपैसिटी होनी चाहिए। हमें और स्टोर्ज की जरूरत हैं चेयरमैन साहब, हैफेड पहले होलसेल्र्ज से अनाज खरीदती थी। एफ.सी.आई. तो पहले ही मार्किट से खरीदती है लेकिन अकेली इसी कार्पोरे ान द्वारा पूरा अनाज खरीदा नहीं जाता था जिससे किसानों को नुक्सान होता था। किसान अपना बाकी अनाज मार्किट

में होल सेल्र्ज को बेचता था जेा मनमाने ढंग से खरीदते थे इससे और किसानों को कम कीमत मिलती थी। हमने इस बारे में रिप्रैजैन्टे ान भी दी थी और चौधरी भजन लाल जी से मिले भी थे। उसका नतीजा यह हुआ कि वे हैफेड को मार्किट में लाये। मेरे हल्के इंदरी में 352 हजार टन अनाज रखने की कैपैसिटी है लेकिन वहां इन एजैंयिों द्वारा एक भी क्विंटल गेहूं नहीं खरीदा गया। अगर हैफेड और एफ.सी.आई. दोनों किसानों से अनाज खरीदें तो किसानों का भाोशण नहीं होगा उनको अच्छी कीमत मिलेगी। मैं एक बात ओर जुडि यरी के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि मैं वकालत का काम करता हूं। वहां जो जुडि यरी स्टाफ है उनको चाहे आप 10 दस्ते दें या चार दस्ते दें लेकिन अच्छी स्टे ानरी दें क्योंकि वहां पब्लिक का काम होता हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है कि सरकार का काम कैसा है। इसके बाद हैल्थ के बारे में कहना चाहता हूं। हैल्थ मिनिस्टर साहिबा ने काफी अच्छा और बढ़ावा देने वाला काम किया है। कई नये हस्पताल खोले गये हैं, कई को एक्सटैंड किया है। कई जगह हैल्थ सैंटर भी खोले गये हैं और रूरल एरियाज में भी डिस्पैंसरियां खोली गई है। हैल्थ मिनिस्टर साहिबा से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे इलाके में रूरल डिस्पैंसरियों की हालत बहुत खराब है। वहां इतना भलाई का काम होता है लेकिन डाक्अर के ब्ैठने के कमरों की छतें बुरी तरह टूटी हुई हैं। कुंजपुरा डिस्पैंसरी की रिपेयर जल्दी से जल्दी की जाये। जहां डाक्टर बैठता है अगर उसकी अच्छी तरह से मुरम्मत की हुई हो, तभी काम चल सकता

है। चेयरमैन साहब, मैं टैक्स के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारे मुख्य मंत्री साहबन दूर की दृश्टि रखते हैं, वे दिली तमन्ना रखते हैं कि किसान को राहत मिले, ये उनकी एम्पलायमैंट के लिए भी स्कीम चालू कर रहे हैं। जो एम्पलायमैंट की स्कीम है इस स्कीम के तहत काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। यह स्कीम बहुत बढ़िया है। जो गांवों में लघु उद्योग लगाए जायेंगे उनसे काफी पढ़े लिखें नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मेरे हल्के में 5 यूनिट लगाए गए है उनमें से 2 यूनिट तो बन कर तैयार हो चुके हैं। इन दो यूनिटों की इन्कम दो–दो, तीन–तीन हजार से कम नहीं है। चेयरमैन साहब, जब सब जगह ये यूनटिस लग गए तो इन्कम काफी बढ़ेगी। इनसे बेकारी घटेगी और प्रोडक ान बढ़ेगी। इनसे स्टेट का भी फायदा होगा। अनएम्पलायमैंट खत्म करने के लिए इससे बेहतर और कोई स्कीम नहीं हो सकती। अब मैं टैक्सों के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने मिल करके एक कमेटी बनाने की प्रोपोजल बनाई है जो इन टैक्सों पर दोबारा विचार करेगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो लैण्ड होल्डिंग्ज टैक्स पर सरचार्ज लगाया है और जो आबियाने पर सरचार्ज लगाया है इन दोनों को विदड्रा करके गरीब किसानों को राहत दें। इससे किसानों की हालत अच्छी होगी।

श्री सभापतिः अब आप वांइड–अप कीजिए।

चौधरी देस राजः अच्छा जी। इसके साथ ही जो कनवेएंस डीड पर स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने का प्रोवीजन किया गया है उसको भी कम किया जाए। क्योंकि गरीब आदमी, तो पैसे की जरूरत के लिए अपनी जमीन बेचता है या रहन करता है लेकिन लेने वाले किसान के लिए भी मजबूरी है क्योंकि उसके ऊपर सीलिंग आ गई, 1952–53 में पजांब सिक्योरिटी आफ लैंड टैनयोर्ज एक्ट आ गया और अब लैंड सीलिंग एक्ट आ गया जिससे वह बेसहारा हो गया और उसकी आवाज न रही लेकिन अब तो आवाज है और उस आवाज के जेरे असर मैं समझता हूं कि हम यहां पर भी और बाहर भी मुख्य मंत्री जी से और उस कमेटी से निवेदन करेंगे कि लैण्ड हेाल्डिग्ज टैक्स पर और आबियाने पर जो सरचार्ज लगाया है इसको विदड्रा करें और इसके साथ ही स्टैम्प ड्यूटी जो बढ़ायी है इसको भी विदड्रा करके किसानों को राहत दें। चेयरमैन साहब, अम मैं भाराब के बारे में कहना चाहता हूं। जैसे कि पीछे भाराब के बारे में जिक्र आया था कि भाराब के ठेकों की काफी नीलामी हो रही है। मैं एमझता हूं कि यदि भाराब पर और टैक्स लगा दिया जाए तो किसी को भी एतराज नहीं होगा। इससे करीब 20 करोड़ का घाटा है और 10 करोड़ रूपए के नए टैक्स लगे हैं यह हमारा घाटा इससे पूरा हो सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो किसानों पर टैक्स लगाए गए हैं इनको वापिस ले करके किसानों को राहत दें। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोनले के लिए मुझे टाईम दिया।

श्री टेक राम (मुंढाल खुर्द): चेयरमैन साहब, हाउस में तीन चार रोज से बजट पर डिस्क ान चल रही हैं। मैं भी अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं। जनता पार्टी की सरकार ने सता सम्भालने से पहले जो वायदे किये थे उन वायदों को उसने पूरा किया है। सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य श्री सुरजेवाला को बताना चाहता था लेकिन वे हाउस में नहीं है। उन्होंने कुछ बातें जनता सरकार के ला–एण्ड आर्डर के बारे में कही थीं। ला एण्ड आर्डर के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले महीने पाकिस्तान के कुछ डकैत आए जो कि दिल्ली सूबे से गुजरते हुए हरियाणा के अन्दर आए थे। उन्होंने भिवानी में एक डाका डाला, अभी वह दूसरी जगह नहीं पहुंच पाए थे कि हरियाणा की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जो पुलिस ने इतनी बहादुरी के साथ काम यिका है उसके लिए मैं तो मुख्य मंत्री जी और होम मिनिस्टर को बधाई देता हूं। जिन पुलिस अफसरों ने यह बहादुरी का काम किया है उनको कोई न कोई जरिया बना करके इनाम के तौर पर पुरस्कार देना चाहिए। चेयरमैन साहब, मेरे हल्के में एक काफी बड़ा गांव है वहां पर दो भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ। उनमें से छोटा भाई कत्ल हो गया। पुलिस उस गांव में गई और उसने चार घण्टे के अन्दर–अन्दर उस कत्ल का सुराग निकाल लिया। पुलिस ने यह काम बड़ी बहादुरी के साथ किया। इसके लिए भी मैं चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को बधाई देता हूं। चेयरमैन साहब, जनता सरकार ने हरिजनों के लिए चौपाल बनाने का जो प्रोग्राम बनाया है वह बहुत ही सराहनीय है। हरियाणा में

जो बड़े–बड़े गांव हैं वहां चौपालैं बनाई गई हैं ताकि हरिजन भाई अपनी बिरादरी को बैठाने के लिए और अपनी बारात ठहराने के लिए उन्हें काम में ला सकें। चेयरमैन साहब, जो अपोजी ान के भाई डिस्क ान में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने हरिजनों के बारे में एक भी भाब्द नहीं कहा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जनता सरकार ने बैकवर्ड क्लासिज को टिकटें भी दी थी और दो परसैंट से 5 परसैंट तक उनकी रिजर्वे ान भी की है जिसकी तरफ कांग्रेस सरकार ने कभी भी ध्यान नहीं दिया था। जनता सरकार ने सिलैक ान बोर्ड का चेयरमैन बैकवर्ड क्लास का बनाया है लेकिन आज तक कांग्रेस सरकार ने कभी भी बैकवर्ड क्लास से कोई चेयरमैन नहीं बनाया था। चेयरमैन साहब, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमैंट बिजली पर कट लगाती थी लेकिन जनता सरकार कोई कट नहीं लगाती है। इसी साल में 16 जार ट्यूबवैल्ज को कनैक ान दिए गए है, कांग्रसे की सरकार ने कभी भी इतने कनैक ान नहीं दिए थे। चेयरमैन साहब, अब मैं फ्लड के बारे में कहना चाहता हूं। बाढ़ एक प्राकृतिक प्रकोप है जिसको कि हम रोक नहीं सकते लेकिन फिर भी गरीबों की सहायता के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने बड़े हौसले के साथ कपड़ा, अनाज और ट्रैक्टर तथा चारा भी पहुंचाया। कांग्रेस सरकार का चीफ मिनिस्टर तो ऐसा था कि वह अपने गले में नोटों की मालाएं डलवाता था लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर के गले में कोई माला डलती है तो वह उतने ही पैसे और मिला करके गांव के विाकस के लिए वापस दे देते हे। चेयरमैन साहब, मैं पानी के बारे

में कहना चाहता हूं कि जनता सरकार ने देहात में पानी काफी मात्रा में पहुंचाया है लेकिन कांग्रेस सरकार ने इतना पानी कभी भी नहीं दिया। इसके लिए भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं। चेयरमैन साहब, कांग्रेस सरकार 30 साल से काफी प्रचार किया करती थी कि हम किसानों के लिए बहुत राहत दे रहे हैं लेकिन उसके मुकाबिले में जनता सरकार ने 2 साल के अन्दर ही किसानों को खाद के लिए और दूसरी हर एक चीज के लिए राहत पहुंचाई है। जनता सरकार ने इस पर साढ़े 63 लाख रूपया खर्च किया है जबकि कांग्रेस सरकार ने कभी भी इतना खर्च नहीं किया था। चेयरमैन साहब, कांग्रेस राज में वाटर सप्लाई स्कीम्ज पर कभी ध्यान नहीं दिया गया लेकिन जनता सरकार ने इस साल साढ़े 58 लाख रूपया वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए रखा है जिससे काफी गांवों को फायदा पहुंचेगा। चेयरमैन साहब, ला एण्ड आर्डर के बारे में चौधरी सुरजेवाला ने जिक्र किया था और कहा था कि ला एण्ड आर्डर बहुत ढीला है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पिछले 30 साल में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा कत्ल हुए। प्रौपर भिवानी में एक बार 30–40 औरतों को गुंडे उठाकर ले गए लेकिन कांग्रेस सरकार उस केस की तफती ा नहीं कर सकी। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपने पिछले कारनामों पर पर्दा डाल रहे हैं और जनता गवर्नमैंट की नुक्ताचीनी कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहला सुझाव यह है कि फर्टिलाइजर जो किसान को मिलती है, उस पर किसान को सबसिडी मिलनी

चाहिए। इसके अलावा किसान को कोआप्रेटिव बैंक से जो कर्जा मिलात है उस पर बड़ा हैवी इन्ट्रैस्ट चार्ज किया जाता है। इसके दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक जो इंडस्ट्रीज को कर्जा देता है या दूसरे बैंक्स इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जो कर्जा देते हैं, वे केवल 4 परसैंट ब्याज चार्ज करते हैं लेकिन किसान से कोआप्रेटिव बैंक ज्यादा ब्याज वसूल करता हैं इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि किसान को भी 4 परसैंट ब्याज पर कर्जा मिलना चाहिए ताकि उस सहूलियत मिले। चेयरमैन साहब, अगला सुझाव ट्रैक्टर कम्पनियों के बारे में है। ये कम्पनियां किसाने को आफत में डाल देती है। जो फर्म ट्रैक्टर बेचती है, उसके एक ट्रैक्टर की कीमत मु कल से 24–25 हजार रूपया है लेकिन किसान को 60–70 हजार रूपये में देती है। इस महंगाई की तरफ सरकार ध्यान दें। इसके अलावा ट्रैक्टर की रिपेयर का खर्चा भी किसाने से बहुत ज्यादा वसूल किया जाता है। इस तरफ भी सरकार ध्यान दे। चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए सी.एम. साहब और गवर्नमैंट के नोटिस में लाना चाहता हूं कि कृशि लेबर के रेट कम किए जाएं, इस तरफ सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड आर.) और पब्लिक हैल्थ के अन्दर गवर्नमैंट ने लेबर चार्जिज 4 रू. और 5 रू. मुकर्रर किये हैं लेकिन कृशि पर लेबर चार्जिज 7–8 रूपये के करीब है जो कि बहुत ज्यादा है। ट्रैक्टर वगैरह की रिपेयर के लेबर चार्जिज भी किसान को बहुत महंगे पड़ते हैं, यह भी आधे रेट पर होने चाहिए यानी आधा रेट गवर्नमैंट दे और आधा किसान दे ताकि किसान पर ज्यादा बोझ न

पड़े। इसके अलावा मैं एम.आई.टी.सी. के बारे में सुझाव दूंगा। आई.पी.एम. साहब, बैठे है। लाइनिंग आफ वाटर कोर्सिज के लिए एस.एफ.डी.ए. पैसा देती है लेकिन सरकार ने कुछ इलाकों को एस. एफ.डी. के परव्यू से एक्सकलूड कर दिया है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट का मुंढाल खुर्द हल्का, इसके अलावा चौधरी जिले सिंह का हल्का, आपके हल्के के कुछ गांव हैं जो एस.एफ.डी.ए. के परव्यू सके निकाले गए हैं। इस प्रकार कुल 7 हल्कों के गांव हैं जिनको पिछले 10 सालों से एस.एफ.डी.ए. से कोई पैसा नहीं मिला। किसान को यह राहत मिलनी चाहिए लेकिन ये एस.एफ.डी.ए. की राहत से टाले गये। यह बात मैं आई.पी.एम. साहब के नोटिस में लाना चाहता हूं। ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, उनसे भी रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि वे इस पर गौर करें और इन सात हल्कों को भी एस.एसफ.डी.ए. के परव्यू में लाया जाए।

एक सदस्यः एस.एफ.डी.ए. से फायदा क्या है।

श्री टेक रामः इससे फायदा यह है कि अगर कोई वाटर कोर्सिज की लाइनिंग करवाये, नहर पक्की करवाये तो उस पर सबसिडी के तौर पर एस.एफ.डी.ए. मदद देती है। 1 लाख पर 10 रूपया फायदा देती है। चेयरमैन साहब, बैकवर्ड क्लासिज का जहां तक ताल्लुक है, इनमें कुछ क्लासिज ऐसी हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। जैसे सांसी, बावडी वगैरा हैं। इन लोगों के रहन सहन का स्टैंडर्ड भी थोड़ा बहुत ऊंचा होना चाहिए। अनुसूचित जातियों में एक वर्ग है जो ऊपर के लैवल पर रहता है, बाकी सब वर्ग नीचे

के लैवल पर रहते हैं। सरकार को अनुसूचित जातियों के हर वर्ग को ऊपर उठाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार ने लैंड टैक्स और वाटर टैक्स पर जो सरचार्ज लगाया है, इसको उसे तहेदिल से वापिस लेना चाहिए। मैं सी.एस. साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि जब तक ये टैक्स खत्म नहीं होंगें, किसान का भला नहीं हो सकता।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए।)

श्री सभापतिः आप सब बैठिए, अहिस्ता आहिस्ता सबको टाईम मिलेगा। अब श्री बलदेव तायल बोलेंगे।

श्री बलदेव तायल (हांसी): चेयरमैन साहब, मैं बजट का समर्थन करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चेयरमैन साहब, थोड़े इतिहास के पन्ने बदलने की आव यकता है। आजादी से पहले एक जमात बनी थी, जिसका विखंडित रूप आज भी आपके सामने है। जिसे कांग्रेस कहते हैं। आजादी से पहले केवल एक ही कांग्रेस थी इंडियन नै ानल कांग्रेस। अब इसका विखंडित रूप हमारे सामने है। ये विखंडित रूप तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते है और 6 भी हो सकते है। उस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, एक क्रांन्ति का नारा दिया था और भारतवर्श की जनता को यह सपना दिखाया था कि आजादी के बाद, भरत की 85 प्रति ात जनता, जो देहातों में रहती है, उनको आर्थिक

स्वाधीनता मिलेगी। उनके खेत फसल से लहलहा उठेंगे, बच्चे हंसेगें, मातायें स्वस्थ होंगी, पुरूश काम धंधे करेंगे, दे ा धन–धान्य से परिपूर्ण होगा। उस कांग्रेस ने तरह तरह के सब्जबाग दिखाये थे, तरह तरह के सपने दिखाये थे लेकिन 30 साल में उसने इस 85 परसैंट जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसके उलट हो गया। देहाती जनता की ओर किसी सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया, अगर कुछ किया है तो यह किया कि अगर सड़क बननी भुरू हुई तो भाहर में, हस्पताल बनना भुरू हुआ तो भाहर में, यूनिवर्सिटी बनी तो भाहर में, गर्जे की जो भी डिवैल्पमैंट का काम था, लोगों की वैल्फेयर का काम था, उसका आरम्भ भाहर से हुआ। 30 साल के बाद हिन्दुस्तान के गगन पर एक नया सितारा उत्पन्न हुआ जिसको जयप्रका ा नारायण के नाम से भारत की जनता भली भांति जानती है। उन्होंने नारा दिया कि सम्पूर्ण क्रांति लाएं। सम्पूर्ण क्रांति से आ ाय है कि हर भारत के नागरिक को अपने अधिकारों का पता हो, अपनी आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए वह सजग हो। उस नारे के फलस्वरूप जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी ने उस समय एक नारा दिया कि आगे से भारत का ग्राम निगलैक्ट नहीं होगा। मैं जनता पार्टी की सरकार को, मुख्य मंत्री महोदय की और वित्त मंत्री महोदय को बहुत–बहुत मुबारिकबाद देता हूं जिन्होंने पहली बार 75.5 परसैन्ट बजट का हिस्सा ग्रामों के उत्थान के लिए रखा है और जिसके अन्दर मेन काम पानी का या ऊर्जा का होना है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) मेरे भाई राव बीरेन्द्र

सिंह जी ने फ्लड के मसले को, इस दयनीय प्रकोप को खासा लाइटली लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि सरकारें आई और चली गई, उन सरकारों ने काफी पैसा भी खर्च किया लेकिन किसी भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि इन फ्लडज को रोकने का कोई स्थाई उपाय किया जाए। जनता सरकार पहली सरकार है जिसने राहत कार्य करने के साथ साथ यह तहैया कर लिया है कि यह जो 50 करोड़ रूपये का साल का नुक्सान हरियाणा को होता है इसका स्थाई रूप से कोई उचित उपाय किया जाए ताकि हरियाणा फ्लड विमुक्त हो जाए और बाढ़ का खतरा न रहे। इसके लिए मैं एक बार फिर मंत्रिमंडल को ओर मुख्यमंत्री जी को मुबारिकबाद देता हूं।

एजुके ान बड़ा महत्वपूर्ण सबजैक्ट है। इस फील्ड के अन्दर भी सरकार ने खासे ठोस कदम उठाए हैं लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में सरकार का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। हमारी युनिवर्सिटीज आज के दिन लगभग क्या बनी हुई है ? They are only manufacturesrs of unemployed graduates and post-graduates. उनकी ि ाक्षा का स्तर वह नहीं है जो होना चाहिए। सरकार एक एक विद्यार्थी पर हारो ंरूपये खर्च करती है। बी.ए. और एम.ए. पास करने के बाद क्लर्क की पोस्ट के लिए भी हमारे नौजवानों को मारा–मारा फिरना पडता है। हमारी दुर्भाग्य देखिए, बी.ए. पास लड़का आज के दिन हरियाणा सरकार के टूरिज्म डिपार्टमैंट के अन्दर वेटर के तौर पर काम करता है। यह

हमारे नौजवानों का दुर्भाग्य है, इसके बारे में मेरा सुझाव इतना है कि एलीमैंटरी ि ाक्षा मैट्रिक तक जौब ओरियंटिड होनी चाहिए। हर स्कूल के साथ कोई न कोई काम की वर्क ाप होनी चाहिए। साथ के साथ उच्च ि ाक्षा केवल उन विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए जो उसके काबिल हो, जो पढ़ने में रूचि रखता हो या आगे चल कर कुछ करके दिखा सके। ये जो वि वविद्यालय है, they should be a real seat of learning instead of manufacturers of these unemloyed graduates. इससे विद्यार्थियों में जो फसट्रे ान है, जो निरा ाा का भाव आया हुआ है वह समाप्त होगा, एजुके ान पर खर्चा कम होगा और ज्यादा से ज्यादा लिटरेसी भी बढ़ेगी। मैं तो सुजैस्ट करूंगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिग्ज बनाने की बजाय, तीन तीन मंजिलें होस्टल बनाने की बाजय भाांति निकेतन टाईप वि वविद्यालय बनने चाहिए। (विघ्न) स्वामी अग्निवे ा जी से मैं क्षमा चाहूंगा कि ये गुरूकुल इत्यादि हैं इनके प्रति मेरी कोई खास श्रद्धा नहीं है। (विघ्न) तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जो यूनिवर्सिटीज का खर्चा है, जो उच्च ि ाक्षा का खर्चा है उसको कम करके ज्यादा से ज्यादा पैसा स्कूल्ज की तरफ लगाना चाहिए और नारी ि ाक्षा की ओर लगाना चाहिए। (विघ्न) अन–एम्पलायमैंट प्रौब्लम, बेरोजगारी का किस्सा सबके सामने है। इसके लिए जनता पार्टी की सरकार ने जो कदम उठाए हैं वे भी सराहनीय है। लघु उद्योग धन्धे, कुटीर उद्योग, ग्रामों में उद्योग आदि लगने से मैं यह समझता हूं कि बेरोजगारी की समस्या समाप्त करने में बहुत प्रोत्साहन मिलेगा लेकिन साथ

ही साथ एक बात सरकार को और सोचनी होगी। वह बात यह है कि ये जा लघु और कुटीर उद्योग हों गे इनसे जो माल बनेगा उसको खपाने का, उसकी मार्किटिंग का, उसकी कम्पीटिटिव मार्किट में स्टैंड करने का इन्तजाम भी सरकार को करना चाहिएं इसके बारे में वित्त मंत्री जी को मैं केवल इतना सुझाव दूगा कि अगर आपने कम्पीटिटिव मार्किट में स्टैंड करना है क्योंकि आज का युग कम्पीटि ान का है, तो यह जो इन्होंने निर्यात कर लगाया है, हरियाणा से बाहर सामान ले जाने पर लगाया है, इस पर दोबारा विचार करें, साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर वित्त मंत्री जी इससे सहमत न हों तो वे नए लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों पर से यह कर माफ कर दें और जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं उन पर चाहे इस कर को लगा कर रखें।

रिजर्वे ान आफ सीट्स के बारे में सरकार फिर बधाई की पात्र है। बैकवर्ड क्लासिज की तरफ तो सरकार ने सोचा है लेकिन साथ ही साथ मैं एक और पद दलित जाति की ओर इसका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज के युग की बात नहीं है बल्कि हजारों वर्श पहले की बात है और भारतवर्श के अन्दर तो सदा सदा से उस जाति के ऊपर अत्याचार होते आए है। अफसोस की बात है कि आज तक उस जाति के लिए, नौकरियों में स्थान सुरक्षित कराने के बारे में या उन्हें आर्थिक स्वाधीनता दिलाने के बारे में कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप पूछेंगे कि वह जाति कौन सी है ? मैं आपसे अर्ज करूंगा कि उस जाति की संख्या,

उस वर्ग की संख्या भारतवर्श में 50 प्रति ात है। वह है नारी जाति। नारियों के लिए आज एजुके ान का कोई भी वि ोश प्रबन्ध नहीं है (विघ्न)। बहिन कमला वर्मा जी कह रही हैं कि उनकी दयनीय द ाा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आज उनकी बहुत ही बुरी हालत है। आप गांवों में जायें, भाहरों में जायें, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वह बहुत ही बुरा हो रहा है। उनको किसी प्रकार की कोई आर्थिक स्वाधीनता नहीं है। क्या वे आज इज्जत के साथ रोटी कमा सकती है ? बिल्कुल नहीं। आज तक किसी भी साथी ने यहां हाउस में उनके बारे में विचार नहीं किया।

चौधरी हरिचन्द हुड्डाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। तायल साहब ने कहा कि नारी की तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। नारी को हम तो सदा से माता का दर्जा देते रहे हैं। हमने सीता को सीता माता का दर्जा दिया। इसी प्रकार से दुर्गा मां को दुर्गा माता का दर्जा दिया। नारी को सदा से ही पूजते चले आ रहे हैं।

श्री मांगे राम गुप्ताः तायल साहब नारी का सुधार करना चाहते हैं, मैं यह सुझाव दूंगा कि इसके लिए एक कारपोरे ान बना दी जाये और उसके चेयरमैन तायल साहब को बना दिया जाए। (हंसी)

श्री बलदेव तायलः मुझे चेयरमैन बनने में कोई एतराज नहीं ब ार्ते श्री मांगे राम जी उसके सदस्य बनने के लिए तैयार हों। (हंसी) उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई उपहास की बात नहीं है। यह बड़ा भारी गम्भीर विशय है। केवल इनकी पूज करने से पेट नहीं भरता है। पूजा करने के साथ–साथ इनको स्वाधीनता भी दीजिए। क्या आप यही चाहते हैं कि वे सदा ही गुलाम रहें ?

चौधरी हरिचन्द हुड्डाः तायल साहब ने आर्थिक स्थिति के बारे में बात की। अर्थ यानी धन तो सदा से ही इनके हाथों में रहा है।

श्री बलदेव तायलः यह ठीक बात है लेकिन मैं तो पूर्ण रूप से स्वाधीनता देने की बात कह रहा हूं। इसलिए मैं सरकार से उनके बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि उनको नौकरियों में भी कुछ न कुछ पद मिलने चाहिएं यानी उनके लिए कुछ पद रिजर्व होने चाहिए।

यहां पर बार–बार अपोजी ान के साथियों की ओर से कार्पोरे ांज के बारे में चर्चा की जा रही है। सरकार ने यह जो चेयरमैन बनाये हैं इनके बारे में बहुत एतराजात उठाये गये। मुझे तो एतराजात का कारण समझ में नहीं आया। जिन कार्पोरे ांज के चेयरमैन एम.एल.एज. को बनाया गया है अगर वे कार्पोरे ांज जनता सरकार के आने से पहले मुनाफे में होती तब तो यह कहा जा सकता था कि सरकार पर उसका बोझा पड़ा है। जब इनको

चेयरमैन बनाया गया था उस वक्त वे घाटे में चल रही थी, इनके बनने के बाद तो घाटा नहीं हुआ। मैं अपने माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी कार्पोरे ांज पीछे बेहद घाटे में रही हैं इसलिए इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है अब से पहले इन कार्पोरे ांज पर सरकारी अफसरों का नियन्त्रण था, लाभ नहीं हो रहा था। एक्सपैरीमैंट के आधार पर इन कार्पोरे ांज के चेयरमेन एम.एल.एज. को बनाया गया। उनको चेयरमैन लगाने के बाद इनमें सुधार ही नहीं हुआ बल्कि मुनाफे में चल रही है। जैसे मिनरल कार्पोरे रूान है, हैन्डलूम कार्पोरे ान है, हरिजन कल्याण निगम है और एग्रोइन्डस्ट्री कार्पोरे ान है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जो चेयरमैन ईमानदारी से और मेहनत से अपना फर्ज निभा रहे हैं, उनको निरा ा मत कीजिए बल्कि उनको आप सहयोग दीजिए। उनको आप यह बतायें कि इस तरह से फाययदा हो सकता है। वे आपके भाई है। आपके साथी है, वे जनता का भला करना चाहते हैं।

अब मैं सरकार का ध्यान कुछ भाहरों की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। गरीब हर जगह पर होता है चाहे कोई भाहर हो या गांव हो। गरीब लोगों को न भाहर है और न ही देहात है। भाहर के अन्दर भी उनकी हालत वही है जो गांव में है। आज रिक ाा वाले की क्या हालत है ? वह फूटपाथ पर सोता है। उसके बच्चे पानी के पाइप में जन्म लेते हैं। सिर पर खली आसमान है और नीचे धरती है। वह अपनी रोजी अपने बाहूबल से कमाता है,

टोकरी ढोता है। भाहरों में आम आदमी गरीब है। भाहरे में भी गरीब तबका लैन्डलैस होता है जिसको आप लेबर कह सकते हैं। चाहे वह लेबर गांव में है या भाहर में है उसकी तरफ उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। उन गरीबों के लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। मैं इस संदर्भ में वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना चाहूंगा कि जो सरकार ने हलवाइयों पर टैक्स लगाया हे उसमें चीजें बतानी चाहिए कि किस किस मिठाई पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। आप क्लीयर करें कि रसगुल्ले पर या गुलाबजामुन पर टैक्स लगाने जा रहे हैं या किसी अन्य चीज पर लगाने जा रहे हैं। गुलाबजामुन और रसगुल्ले पर बे ाक टैक्स लगा दें लेकिन मुरी गुजाकिर ा है कि हर मिठाई पर टैक्स न लगायें। जो कास्टली चीजें हैं उन पर टैक्स लगायें आम आदमी जो खाता है उस पर टैक्स न लगायें। जैसे कि हलवाई मिठाई भी बनाता है और उसके साथ ही साथ वह दो रूपए के अन्दर आम आदमी को, आम जनता को रोटी भी देता है क्योंकि देहात का आदमी, कोई गरीब मजदूर, कोई गरीब व्यापारी, और कोई गरीब रिक ोवाला मौंटव्यू जैसे बड़े होटल के अन्दर रोटी नहीं खा सकता। उसका रोटी खाने का साधन रेहड़ी वाला, ढाबे वाला या तंदूर वाला हो सकता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो ऐसे आइटम हैं जिनको कि अमीर लोग खाते हैं उन पर अव य टैक्स लगाओ परन्तु गरीब के अन्न पर टैक्स न लगाओ।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री का ध्यान और खास तौर से पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर का ध्यान हांसी निर्वाचन क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। मुख्य मंत्री ने एक बार अनाउन्स किया था कि हर हल्के के अन्दर पांच किलोमीटर सड़क अव य बना दी जाएगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हांसी निर्वाचन क्षेत्र में अब तक केवल 2.1 किलोमीटर सड़क इन दो सालों में बनी है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हांसी की म्यूनिसिपल कमेटी की द ा बड़ी दयनीय है। उसके पास तनख्वाह तक देने को पैसा नहीं है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्शित करूंगा कि जाहं दस–दस लाख रूपया म्यूनिसिपल कमेटीज को दिया है, इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि हर म्यूनिसिपल कमेटी की आर्थिक रिपोर्ट मंगवा लें और उसके मुताकिब थोड़ा थोड़ा अनुदान सब को दें और मुझे वि वास है कि अबर वे न्याय करेंगे तो हांसी को अव य कुछ न कुछ मिलेगा। इस बारे में मैं एक बात की और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हांसी भाहर और हांसी निर्वाचन क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है। हजारों मकान गिर जाते हैं। इस काम के लिए सैन्टर की तरफ से अब तक जो भाहरों के लिए ग्रान्ट आई है उसमें से एक पैसा भी हांसी भाहर को नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कि जो बाढ़ग्रस्त भाहर हैं उनको अनुदान अव य दें।

श्री भाम ोर सिंहः आर.एस.एस. में जाने लगो तब ग्रान्ट मिलेगी। भााखा में जाया करो तब ग्रान्ट मिलेगी। (व्यवधान)

श्री बलदेव तायलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाई भाम ेर सिंह को याद दिलाना चाहता हूं कि आप आर.एस.एस. का मजाक उड़ाना चाहते हैं इनकी सरकार ने आर.एस.एस. के हजारों निरपराध लोगों को जेल में डाल कर दु:ख दिया था, उनको जेलों में सड़ाया था। मैं टूरिजम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि जनता सरकार को बने दो वर्श बीत गए हैं एक बार वे हांसी का दौरा कर लें। तब उनको मालूम होगा कि वहां क्या हालत है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां पर एक और ए योरैंस दी गई थी और वह ए योरैंस डा. मंगल सैन जी ने दी थी। सदन में जुडि ियाल सर्विसिज के बारे में एक रैजोल्यू ान आया था जिसमें कहा गया था कि जुडि ियल सर्विसिज को एग्जैक्टिव सर्विसिज के बराबर लाया जाए, उनके बराबर का ग्रेड दिया जाए। मेरा कहना यह है कि अभी तक सिर्फ नौकरी में बराबरी दी है, न तो उनको बराबर का हाउस रेंट दिया है, न कनविएंस अलाउन्स दिया है, न टेलिफोन की सहूलियत दी है और मेरे ख्याल में सिलैक ान ग्रेड दिया है .....

कई आवाजें: सिलैक ान ग्रेड तो दे दिया है।

श्री बलदेव तायलः दे दिया गया है तो बहुत अच्छा किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक आईटम के बारे में और कहना चाहता हूं और वह है पैसेन्जर टैक्स। जो पैसेन्जर टैक्स बढ़ाया है, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उसको थोड़ा कम कर

दिया जाए। यह आम आदमी पर एक बोझा है। इसको अव य कम कर दिया जाए, इसमें थोड़ी तरमीम कर दी जाए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी हरफूल सिंह ज्यादा चिन्तित हैं इसलिए मैं इन्हीं भाब्दों के साथ समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री फतेह चन्द विज (पानीपत): उपाध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर जो डिस्क ान हो रही है (व्यवधान) उसके बारे में हमारी तरफ के साथियों ने और अपोजी ान के साथियों ने अपने अपने विचार रखे हैं। हमारे अपोजी ान के साथियों को तो इस बजट में कोई अच्छी बात नजर नहीं आई। इस बारे में मैं एक बात सुनाना चाहता हूं। एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता था। उसको मौलवी ने कहा कि भई तुम मुसलमान होकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो ? उस मुसलमान ने कहा कि कुरान भारीफ में लिखा है कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। मौलवी ने हैरान कोकर पूछा कि कुरान भारीफ में तो कही नहीं लिखा है कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। उस मुसलमान को कुरान भारीफ का सफा याद था उसने कुरान मंगवाई। कुरान भीरफ में लिखा था कि नमाज न पढ़ो ओर आगे लिखा था कि अगर तुम पाक न हो। उस मुसलमान ने केवल इतना पढ़ा कि नमाज न पढ़ो ओर आगे वाले हिस्से पर हाथ रख लिया। मौलवी ने कहा कि भई सारा पढ़ो। उस मुसलमान ने कहा कि जो मेरे मतलब की बात थी मैंने उसको ले लिया है। इसी तरह से इन भाईयों को बजट के बारे मं केवल नुक्ताचीनी करनी

थी और इसके सिवाए इनको बजट में कोई बात नजर नहीं आई। डिप्टी स्पीकर साहब दो साल से जब से जनता सरकार आई हैं, राव साहब यहां सदन में यह दुआ कर रहे हैं कि हर साल ऐसी मुसीबतें आती रहें। यानी 1982 तक इसी तरह की मुसीबतें आती रहें। कितने अफसोस की बात है कि जो आदमी हरियाणावासी हो, जो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर रहा हो, आज वह हरियाणा के लिए इस तरह की कामना करे कि हरियाणा में मुसीबतें आती रहें। (ोम, ... भोम की आवाजें)। डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ भाईयों ने यहां पर देहाती और भाहरी का जिक्र किया। मेरी उनसे नम्र निवेदन है कि एक राज्य के लिए एक स्टेट के लिए भाहरों का होना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन की बैठक आज बाद दोपहर 3. 00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.00 Hours

(The Sabha then adjourned till 3.00 p.m. oned Wednesday the 22nd March, 1979)